RNI No. - UPHIN/2023/85551

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

द न्यूज़ कॉर्नर

मार्च 2025 • वर्ष : 02 अंक : 12 • मूल्य : 30/-



राजनीतिक दलों में भितरघात का दंश

सोलर रूफटॉप लगवाएं

आकर्षक अनुदान एवं बिजली बिल में राहत पाएं



टोल फ्री नं0 **155243**
सोलर रूफटॉप की स्थापना/ जानकारी एवं किसी भी समस्या के लिए संपर्क करें।

पीएम सूर्य घर : मुफ़्त बिजली योजना

योजना के अंतर्गत 300 यूनिट मुफ़्त बिजली

संयंत्र की क्षमता	केंद्र सरकार का अनुदान (रु.)	राज्य सरकार का अनुदान (रु.)	कुल अनुमन्य अनुदान (रु.)
1 KW	30,000	15,000	45,000
2 KW	60,000	30,000	90,000
3 KW	78,000	30,000	1,08,000
4 KW	78,000	30,000	1,08,000
5 KW	78,000	30,000	1,08,000

- प्लांट की अनुमानित लागत ₹60,000 प्रति किलोवाट।
- सोलर पैनलों की कार्य क्षमता अवधि लगभग 25 वर्ष।
- 3 KW का प्लांट मात्र ₹1800/- की आसान ईएमआई पर लगवाएं।
- मात्र 7% की ब्याज दर पर बैंक लोन।
- सोलर प्लांट कमीशनिंग के उपरांत सब्सिडी डी.बी.टी. द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में।
- बिजली बिल में दो तिहाई तक की बचत।
- यूपीनेडा में पंजीकृत वेंडर के माध्यम से ही सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाएं। वेंडर का चयन ध्यानपूर्वक करें।

योजना का लाभ उठाने के लिए शीघ्र आवेदन करें -

https://pmsuryaghar.gov.in/

किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत के लिए 155243 पर संपर्क करें
या वेबसाइट https://upnedasolarsamadhan.in पर जाएं।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष : 02 ● अंक : 12

सम्पादक
सैय्यद आसिफ़ रज़ा जाफ़री
प्रबन्ध सम्पादक
दीपक कृपलानी
समाचार सम्पादक
शारिब जाफ़री
स्थानीय सम्पादक, उत्तराखण्ड
शबीह अहमद रिज़वी
विधि सलाहकार
सैय्यद आफ़ताब अहमद
धर्मेंद्र सिंह
पंजीकृत कार्यालय
7, लोकमान्य तिलक मार्ग, डालीबाग
कालोनी, हज़रतगंज, लखनऊ
कॉरपोरेट कार्यालय
303 गोल्डेन हैबिटेड अपार्टमेंट, मदन मोहन
मालवीय मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ-226001
ब्यूरो कार्यालय-नई दिल्ली
डी-864, एलजीएफ, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी
नई दिल्ली-110025
ब्यूरो कार्यालय-मुम्बई
पुष्पक को-ऑपरेटिव सोसाइटी, बी-10 बिल्डिंग
प्रथम तल, फ्लैट नं. 14 खीरानगर, सांताक्रूज वेस्ट
एसवी रोड, मुम्बई।
ब्यूरो कार्यालय-बेंगलुरु
हॉउस नं. 3/9 ग्राउंड फ्लोर, 3 क्रास शमाना
गार्डन, पोस्ट-आडुगोडी, बेंगलुरु-560030
RNI No. - UPHIN/2023/85551

स्वामी, मुद्रक-प्रकाशक सैयद आसिफ़ रज़ा जाफ़री द्वारा नीलम प्रिन्टिंग प्रेस 41/381 नरही लखनऊ-226001 यूपी से मुद्रित कराकर 7, लोकमान्य तिलक मार्ग, डालीबाग कालोनी, हज़रतगंज, लखनऊ 226001 (उ.प्र.) से प्रकाशित।

E-mail :
editor@newscorner.co.in
Website :
www.newscorner.co.in
Ph. No : 0522-2235101, 9415233786

विशेष सूचना

पत्रिका से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों से संपादकीय परिवार की सहमति होना आवश्यक नहीं है। सभी, लेख, लेखक की भावना एवं विचारों की अभिव्यक्ति है, जिसके लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होगें।

समस्त रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं यह पत्रिका/ लेखकों/ पाठकों/ पत्रकारों द्वारा भेजी गई अनिमंत्रित सामग्री को वापस लौटाने की गारंटी नहीं लेती है।

इस अंक में...



शिवराज सिंह चौहान या किरेन रिजिजू ...Pg08



परिसीमन पर उत्तर और ...Pg12



राजनीतिक और पारिवारिक ...Pg18



उर्दू जुबान पर सियासत ...Pg20



औरंगजेब की कब्र उखाड़ ...Pg28



बिहार फतेह की तैयारी में ...Pg36



रिलायंस को झटका ...Pg38

सम्पादकीय



सैय्यद आसिफ़ रज़ा जाफ़री

स्टारलिंक का भारत में पदार्पण

धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस का सीडीएमए फोन लांच करते हुए कहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। यह नारा सिर्फ एक विज्ञापन की टैगलाइन नहीं था, बल्कि एक सपना था–सपना एक ऐसे भारत का, जहाँ संचार की ताकत हर हाथ में हो, हर कोने तक पहुँचे। रिलायंस के संस्थापक ने अपने समय में टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी, जिसने आम आदमी को सस्ती कॉलिंग और कनेक्टिविटी का तोहफा दिया। आज, लगभग दो दशक बाद, उनका यह सपना एक नई उड़ान भरने को तैयार है–लेकिन इस बार बागडोर किसी और के हाथ में है। एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में दस्तक देने वाली है, और इसके साथ ही देश के डिजिटल परिदृश्य में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। सवाल यह है कि स्टारलिंक का आगमन क्या बदलाव लाएगा? क्या यह वास्तव में धीरूभाई के सपने को पूरा करेगा, या इसके अपने जोखिम और चुनौतियाँ भी होंगी?

स्टारलिंक, स्पेसएक्स की सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवा, भारत में जल्द ही शुरू होने की कगार पर है। 11 मार्च 2025 को भारती एयरटेल के साथ साझेदारी की घोषणा ने इसकी राह को और पक्का कर दिया। यह सेवा कम ऊँचाई पर चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराएगी। जहाँ मौजूदा टेलीकॉम कंपनियाँ टावरों और फाइबर ऑप्टिक्स पर निर्भर हैं, वहीं स्टारलिंक अंतरिक्ष से सीधे कनेक्टिविटी देने का वादा करती है। इसका लक्ष्य है–शहरों से लेकर गाँवों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक, हर जगह तेज और सस्ती इंटरनेट सुविधा पहुँचाना। भारत में इंटरनेट क्रांति कोई नई बात नहीं है। जियो ने 2016 में 4 प्रतिशत की लहर लाकर डेटा को सस्ता और सुलभ बनाया था। लेकिन आज भी देश के ग्रामीण इलाकों में करीब 30 फीसदी आबादी इंटरनेट से वंचित है। ट्राई के आँकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2025 तक भारत में 92 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, पर पहाड़ी राज्य, पूर्वोत्तर और दूरदराज के गाँव अभी भी कनेक्टिविटी के मामले में पीछे हैं। स्टारलिंक की निगाह इन्हीं भारतीय यूजर्स पर है, जो इतनी बड़ी संख्या में किसी अन्य देश में उपलब्ध नहीं है। जियो और एयरटेल से करार के बाद भारी संख्या में मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स एक झटके में स्टारलिंक के कदमों में होंगे। स्टारलिंक के भारत में प्रवेश से कई बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों पर पड़ेगा। जहाँ जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसे दिग्गजों के लिए टावर लगाना और फाइबर बिछाना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहा, वहाँ स्टारलिंक का सैटेलाइट नेटवर्क बिना बुनियादी ढाँचे के इंटरनेट पहुँचा सकता है। इससे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल बैंकिंग जैसी सेवाएँ उन गाँवों तक पहुँचेंगी, जो अब तक इससे अछूते थे।

दूसरा बदलाव प्रतिस्पर्धा का होगा। मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों को स्टारलिंक से कड़ी टक्कर मिलेगी। जियो ने जहाँ डेटा की कीमत को 20 रुपये प्रति जीबी से घटाकर 5 रुपये तक पहुँचाया था, स्टारलिंक इससे भी सस्ती दरों का वादा कर रहा है। इसके अलावा, इसकी स्पीड 100-200 Mbps तक हो सकती है, जो मौजूदा 4G और यहाँ तक कि शुरुआती 5G से भी बेहतर है। इससे न केवल यूजर्स को फायदा होगा, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सेवाएँ बेहतर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

तीसरा असर डिजिटल अर्थव्यवस्था पर होगा। भारत सरकार का डिजिटल इंडिया अभियान स्टारलिंक के साथ नई रफ्तार पकड़ सकता है। छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप्स, और फ्रीलांसर उन इलाकों में भी काम कर सकेंगे, जहाँ पहले इंटरनेट की कमी थी। उदाहरण के लिए, हिमाचल के लाहौल-स्पीति या अरुणाचल के दूरदराज गाँवों में अब ऑनलाइन मार्केटप्लेस शुरू हो सकेंगे। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा और शहरी-ग्रामीण डिजिटल खाई को कम करेगा, लेकिन स्टारलिंक का आगमन सिर्फ सुनहरे वादों तक सीमित नहीं है–इसके साथ कई चुनौतियाँ भी हैं। पहली चुनौती नियामक मंजूरी की है। भारत सरकार ने अभी तक स्टारलिंक को हरी झंडी नहीं दी है। सुरक्षा और डेटा गोपनीयता इसके बड़े मुद्दे हैं। सैटेलाइट के जरिए डेटा सीधे विदेशी सर्वरों तक जाएगा, जिससे संवेदनशील इलाकों–जैसे जम्मू-कश्मीर या पूर्वोत्तर–में इसका दुरुपयोग होने का खतरा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इसे पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहती है, ताकि आपात स्थिति में इंटरनेट बंद करने की शक्ति उसके पास रहे।

दूसरी चुनौती लागत की है। स्टारलिंक का दावा है कि यह सस्ता होगा, लेकिन शुरुआती सेटअप–जैसे सैटेलाइट डिश और इंस्टॉलेशन–की कीमत 40,000 से 50,000 रुपये तक हो सकती है। ग्रामीण भारत में जहाँ औसत मासिक आय 10,000 रुपये से कम है, यह कीमत बाधा बन सकती है। अगर स्टारलिंक इसे सब्सिडी या साझेदारी के जरिए सस्ता नहीं कर पाया, तो यह शहरी मध्य वर्ग तक ही सीमित रह सकता है। तीसरा जोखिम पर्यावरण का है। स्टारलिंक के हजारों सैटेलाइट्स पहले से अंतरिक्ष में हैं, और भारत में विस्तार के लिए और लॉन्च होंगे। इससे अंतरिक्ष कचरा (स्पेस डेब्रिस) बढ़ेगा, जो भविष्य में दूसरी सैटेलाइट सेवाओं के लिए खतरा बन सकता है। खगोलशास्त्रियों ने भी चिंता जताई है कि ये सैटेलाइट्स रात के आकाश को प्रभावित कर रहे हैं। धीरूभाई अंबानी ने जब 'कर लो दुनिया मुट्ठी में' का नारा दिया था, तो उनका मकसद था कि हर भारतीय के पास संचार की ताकत हो। रिलायंस इन्फोकॉम ने 2002 में सस्ते फोन और कॉल रेट्स के साथ इसे साकार किया था। आज एलन मस्क का स्टारलिंक उसी सपने को नई ऊँचाइयों पर ले जाना चाहता है। लेकिन अंतर साफ है–धीरूभाई का सपना देसी था, भारत की मिट्टी से जुड़ा था, जबकि स्टारलिंक एक वैश्विक परियोजना है, जिसकी जड़ें अमेरिका में हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या स्टारलिंक भारत की जरूरतों को समझ पाएगा? धीरूभाई ने मसालों से लेकर पॉलिएस्टर तक, भारत की माँग को पहचाना और उसे पूरा किया। क्या मस्क की कंपनी भी ऐसा कर पाएगी, या यह सिर्फ एक बाहरी तकनीक का प्रदर्शन बनकर रह जाएगा?

भारत में स्टारलिंक का आगमन सियासी बहस का मुद्दा भी बन सकता है। विपक्ष इसे विदेशी कंपनियों के दबदबे के रूप में देख रहा है, हाल ही में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि भारत सरकार सबकुछ बेच रही है। संचार नेटवर्क विदेशी कंपनी के हवाले करना देश की सुरक्षा के साथ खतरा है। जबकि सरकार इसे डिजिटल प्रगति का प्रतीक मान रही है। भारती एयरटेल और जियो के साथ साझेदारी से यह संकेत मिलता है कि सरकार इसे पूरी तरह विदेशी हाथों में नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन अगर यह सेवा सस्ती और सुलभ हुई, तो जनता इसे हाथोंहाथ लेगी। सामाजिक स्तर पर, यह कनेक्टिविटी का लोकतंत्रीकरण कर सकता है। गाँव की पंचायतें ऑनलाइन होंगी, बच्चे डिजिटल क्लास ले सकेंगे, और किसान मौसम व बाजार की जानकारी सीधे प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही डेटा गोपनीयता और डिजिटल असमानता का खतरा भी बढ़ेगा। स्टारलिंक का भारत में प्रवेश धीरूभाई के सपने को सच करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। यह इंटरनेट को हर कोने तक ले जाएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। लेकिन इसके लिए सरकार को सुरक्षा, लागत, और नियंत्रण के मुद्दों पर सतर्क रहना होगा। अगर यह सिर्फ शहरों तक सीमित रहा या महँगा साबित हुआ, तो यह धीरूभाई के उस सपने से दूर ही रहेगा, जो हर भारतीय के लिए था। एलन मस्क की यह उड़ान भारत को दुनिया से जोड़ने का मौका है, लेकिन इसे धरती पर उतारने के लिए भारतीय संदर्भों को समझना होगा। धीरूभाई ने जो मुट्ठी में दुनिया करने का सपना देखा था, उसे स्टारलिंक पूरा कर सकता है, बशर्ते यह भारत की आत्मा को छू सके। यह एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है, या फिर एक नई चुनौती। समय ही बताएगा कि यह उड़ान कितनी ऊँची और कितनी दूर तक जाती है।



हर दल में घर का भेदी
चुनाव दर चुनाव ढह रहा किला

''घर का भेदी लंका ढाये'' - यह पुराना मुहावरा रामायण की उस घटना से लिया गया है, जब रावण का अपना भाई विभीषण उसकी हार का कारण बन गया था। भारतीय राजनीति में यह कहावत आज हर राजनीतिक दल के लिए सच साबित हो रही है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद और प्रमुख नेता राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं और निकाय चुनाव के पूर्व उम्मीदवारों की सभा को संबोधित करते हुए इसी ओर इशारा किया। राहुल ने कहा, 'गुजरात कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं - एक वो जो जनता के साथ खड़े हैं और जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा बस्ती है और दूसरे वो जो जनता से कटे हुए हैं, जिनमें से आधे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मिले हुए हैं।' इस बयान ने न केवल कांग्रेस के भीतर, बल्कि देश की सियासत में भितरघातियों की मौजूदगी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।

सैय्यद आसिफ़ रज़ा जाफ़री

नई दिल्ली। हर राजनीतिक दल में विरोधी गुटों का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज के तकनीकी युग में जब सबूत और घटनाएं कैमरे में कैद हो जाती हैं, तो सवालों की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इस विशेष रिपोर्ट में हम हर प्रमुख दल में भितरघात की घटनाओं को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये घर के भेदी अपने-अपने दलों के किले को ढहाने में लगे हैं।

गुजरात से राहुल गांधी ने भितरघातियों को दिया कड़ा संदेश

कांग्रेस में भितरघात का लंबा इतिहास

कांग्रेस, जो कभी देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी रही, आज भितरघात के संकट से जूझ रही है। राहुल गांधी का गुजरात में दिया गया बयान इस बात का सबूत है कि पार्टी नेतृत्व इस समस्या को गंभीरता से ले रहा है। राहुल ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़े तो 30-40 लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए, जो अंदर से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। यह बयान कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार का सामना कर रही है, और हर हार के पीछे भितरघात को एक बड़ी वजह माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों में उसे सत्ता से बाहर

होना पड़ा। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और कांग्रेस की सरकार गिरा दी। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की खींचतान ने पार्टी की एकता को कमजोर किया। हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हार ने नेतृत्व को सकते में डाल दिया। इन सभी हार के पीछे भितरघात की कहानियां साफ दिखाई देती हैं।

कांग्रेस के भीतर एक और सनसनीखेज चर्चा जोरों पर है - रॉबर्ट वाड्रा और भाजपा के बीच कथित डील। वायनाड से सांसद चुने जाने के बाद प्रियंका गांधी की वह आक्रामकता गायब हो गई है, जो उन्हें इंदिरा गांधी की छवि देती थी। पहले जहां प्रियंका हर मुद्दे पर भाजपा को घेरने में आगे रहती थीं, वहीं अब उनकी चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। दूसरी ओर, भाजपा भी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अब कोई बयानबाजी नहीं कर रही, जो पहले एक प्रमुख मुद्दा हुआ करता था। क्या यह सब एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है? यह सवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है।

बसपा में आकाश का उतार-चढ़ाव

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में भी भितरघात की कहानी कम रोचक नहीं है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया था। आकाश ने कम समय में अपनी लोकप्रियता बढ़ाई और भाजपा पर तीखे हमले किए। उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही थी और युवा वर्ग में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में ही मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बताकर सभी पदों से हटा दिया। बाद में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

इस फैसले को जनता सत्ता से सौदेबाजी की नजर से देख रही है। कई लोगों का मानना है कि आकाश की बढ़ती लोकप्रियता मायावती को असहज करने लगी थी, या फिर यह कदम किसी बड़े सियासी समझौते का हिस्सा था। बसपा के भीतर भी यह चर्चा है कि आकाश को हटाने के पीछे कुछ नेताओं का हाथ था, जो पार्टी की कमान अपने हाथ में रखना चाहते थे। क्या यह भी भितरघात का एक रूप था? यह सवाल बसपा के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर रहा है।

महाराष्ट्र में टूट का खेल

महाराष्ट्र में भितरघात की कहानी सबसे स्पष्ट रूप में सामने आई। शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर पार्टी को दो फाड़ कर दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। इसके बाद एनसीपी में अजित पवार ने विद्रोह किया और



शशि थरूर की नाराजगी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भी पार्टी से अपनी नाराजगी जाहिर की है। फरवरी 2025 में एक मलयालम पॉडकास्ट में थरूर ने कहा, मैं कांग्रेस के लिए उपलब्ध हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास समय बिताने के कई अन्य विकल्प हैं। उन्होंने साहित्यिक कार्यों और व्याख्यानों का जिक्र करते हुए कहा कि वह राजनीति के बाहर भी सक्रिय रह सकते हैं। थरूर ने केरल कांग्रेस में नेतृत्व के अभाव की बात उठाई और संकेत दिया कि उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, कई कार्यकर्ता मानते हैं कि केरल में कांग्रेस में एक नेता की कमी है। सर्वेक्षणों में मैं नेतृत्व के मामले में आगे हूं, फिर भी मुझे स्पष्ट भूमिका नहीं दी जा रही। इस बयान को कुछ लोगों ने उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के रूप में देखा, तो कुछ ने इसे पार्टी छोड़ने की चेतावनी माना। हालांकि, थरूर ने बाद में सफाई दी कि उनकी बात को गलत समझा गया और वह केवल अपनी उपयोगिता पर सवाल उठा रहे थे, न कि पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे।



रामगोपाल यादव की पर्ची का राज

समाजवादी पार्टी (सपा) में भितरघात की आंच भी कम नहीं है। 11 मार्च 2025 को संसद भवन के मकर द्वार पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पर्ची थमाते हुए कैमरे ने कैद कर लिया। इस घटना ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। पर्ची में क्या लिखा था, यह सवाल हर किसी की जुबान पर है। जब पत्रकारों ने राम गोपाल से पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोड वर्ड में है। इस घटना ने सपा के भीतर पहले से चल रही भितरघात की चर्चा को और हवा दे दी। सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पहले ही राम गोपाल पर सरकार से मिलीभगत का आरोप लगा चुके हैं। आजम का कहना था कि राम गोपाल ने उन्हें फंसाने के लिए सत्ता के साथ सौदेबाजी की। इससे पहले बजट सत्र के दौरान राम गोपाल और भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद की दोस्ताना बातचीत का वीडियो भी वायरल हुआ था। सपा समर्थक अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या राम गोपाल पार्टी के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं?

उपमुख्यमंत्री बन गए। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बंपर जीत हुई और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, जबकि शिंदे और पवार उनके डिप्टी बन गए। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना और अजित पवार गुट को असली एनसीपी का दर्जा दे दिया। यह सवाल उठता है कि क्या यह सब भितरघात का नतीजा था? शिंदे और पवार की बगावत ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों को कमजोर कर दिया। कई लोग मानते हैं कि भाजपा ने इस भितरघात को हवा दी और इसका फायदा उठाया।

भाजपा का पलटवार

राहुल के बयान पर भाजपा ने तंज कसा। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी कांग्रेस के 140 साल के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष हैं। उनका यह बयान कांग्रेस की आंतरिक दुर्गति और उनकी विचित्र मनःस्थिति को दिखाता है। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि जब से सोनिया और राहुल गांधी का दौर आया, गुजरात में कांग्रेस की हालत बद से बदतर हुई है। ऐसा नहीं है कि भाजपा इससे अछूती रही है। भाजपा में भी समय समय पर इस तरह भितरघात के मामले सामने आते रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हार और भितरघात के आरोप

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को अप्रत्याशित झटका लगा। पार्टी ने 2019 में 62 सीटें जीती थीं, लेकिन 2024 में यह संख्या घटकर 33 पर आ गई। हार के बाद कई भाजपा उम्मीदवारों ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भितरघात का आरोप लगाया। रामपुर से भाजपा उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने हार के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ-साथ पार्टी के कुछ नेताओं के असहयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, पार्टी संगठन को उन लोगों के बारे में बताया गया है।

इसी तरह, मोहनलालगंज से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने हार के बाद कहा कि कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ काम किया और नेतृत्व को इसकी जानकारी है। श्रावस्ती में भाजपा के स्थानीय नेताओं ने एक पूर्व सांसद पर आरोप लगाया कि उन्होंने ब्राह्मण और कुर्मी मतदाताओं को पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए उकसाया। लालगंज से नीलम सोनकर ने भी हार का ठीकरा स्थानीय पदाधिकारियों पर फोड़ा, जिन्होंने कथित तौर पर सपा उम्मीदवार की मदद की। इन मामलों में एक समान बात थी - नेताओं का मानना था कि पार्टी के भीतर से ही उनकी हार की साजिश रची गई।

गुजरात में राहुल ने फूंका चुनावी बिगुल



गुजरात में राहुल गांधी ने दिसंबर 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए भितरघातियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 40त्न वोट हैं और सिर्फ 5 प्रतिशत वोट बढ़ने से भाजपा खत्म हो जाएगी। तेलंगाना का उदाहरण देते हुए, जहां कांग्रेस ने 22 प्रतिशत वोट बढ़ाया था, राहुल ने कहा, गुजरात में हमें सिर्फ 5 प्रतिशत की जरूरत है। राहुल ने पार्टी नेताओं को दो खेमों में बांटा - एक जो जनता के साथ है, और दूसरा जो भाजपा से मिला हुआ है। उन्होंने कहा, गुजरात ने कांग्रेस को मूल नेतृत्व दिया, लेकिन आज हम जनता को दिशा नहीं दिखा पा रहे। राहुल ने सुझाव दिया कि रेस के घोड़ों को रेस में और बारात के घोड़ों को बारात में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर किसी नेता का हाथ कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए।

गुजरात में 1998 से सत्ता से बाहर कांग्रेस को राहुल अब नई दिशा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता नया विकल्प चाहती है, लेकिन पार्टी नेतृत्व उसे रास्ता नहीं दिखा पा रहा। राहुल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता से सीधे जुड़ें और भितरघातियों को बाहर का रास्ता दिखाएं। राहुल के बयान को कांग्रेस के भीतर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। गांधी परिवार के करीबी रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने राहुल का समर्थन करते हुए कहा, ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में आरामदायक स्थिति में बैठे हैं। वे नए चेहरों को आगे नहीं आने देना चाहते। मुमताज ने कहा कि उनका परिवार तीन पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ ईमानदारी से जुड़ा रहा है, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। वहीं, कुछ नेताओं का मानना है कि राहुल का यह बयान पार्टी में और बंटवारा पैदा कर सकता है। एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, भितरघात की बात ठीक है, लेकिन इसे सार्वजनिक मंच पर उठाने से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट सकता है।

आप में आतिशी का विवाद



आम आदमी पार्टी (आप) में भी भितरघात की कहानी सामने आई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आतिशी के नाराज होने की खबरें थीं कि अगर पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। आतिशी को लग रहा था कि उनकी मेहनत और योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। नतीजे आए तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरे हार गए और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन आतिशी अपनी सीट जीतने में कामयाब रहीं। हार के बाद आतिशी के ठुमकों पर सवाल उठे। कुछ लोगों का मानना था कि वह पार्टी की हार का फायदा उठाकर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थीं। आप के भीतर यह चर्चा जोरों पर रही कि क्या आतिशी ने पार्टी के खिलाफ कोई रणनीति बनाई थी। हालांकि, इसकी कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह घटना आप में भी भितरघात की संभावना को दर्शाती है।

हरियाणा में विधानसभा चुनाव व असंतोष

2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा। गुरुग्राम में आयोजित एक बैठक में पार्टी ने हार के कारणों की समीक्षा की। कार्यकर्ताओं के असंतोष, भितरघात और विपक्ष को हल्के में लेने को प्रमुख वजह माना गया। कुछ नेताओं ने हार के लिए उन लोगों पर निशाना साधा, जो हारे हुए नेताओं को समीक्षा की जिम्मेदारी देने के पक्ष में थे। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिश की, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

झारखंड में हार का विश्लेषण

2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद भी भितरघात का मुद्दा उठा। पार्टी की एक आंतरिक बैठक में राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष और झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हार के कारणों पर चर्चा की। नेताओं ने ÷आंतरिक तोड़फोड़÷ को हार की एक वजह बताया। स्थानीय नेताओं का मानना था कि कुछ सीटों पर पार्टी के भीतर गुटबाजी के कारण हार हुई। इसके अलावा, नए आदिवासी और ओबीसी चेहरों की कमी को भी एक समस्या माना गया, जिसका फायदा जेएमएम जैसे दलों ने उठाया।

महाराष्ट्र में मुंबई नॉर्थ ईस्ट का मामला

2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर भाजपा की हार के बाद कार्यकर्ताओं ने विधायकों पर भितरघात का आरोप लगाया। उम्मीदवार मिहिर कोटेचा को शिवसेना (यूबीटी) के संजय दीना पाटिल ने हराया। मुलुंड में कोटेचा ने 60,442 वोटों की बढ़त हासिल की, लेकिन घाटकोपर पूर्व और पश्चिम में खराब प्रदर्शन के लिए विधायकों को जिम्मेदार ठहराया गया। कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि कुछ विधायकों ने पर्याप्त प्रचार नहीं किया और एक पूर्व सांसद ने भी सक्रिय भागीदारी नहीं दिखाई।

भितरघात का अंत कब?

हर दल में भितरघात की यह कहानी नई नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा, आप, शिवसेना और एनसीपी - हर पार्टी अपने 'घर के भेदियों' से परेशान है। तकनीक के इस दौर में जब सबूत सामने आते हैं, तो सियासी भूचाल आना तय है। राहुल गांधी का गुजरात में दिया गया बयान अब सभी दलों में आत्ममंथन का कारण बन गया है। क्या भितरघातियों पर लगाम लग पाएगी, या घर के भेदी हर बार किला ढहाते रहेंगे? यह सवाल 2027 के गुजरात चुनाव और आने वाले दिनों में सियासत की दिशा तय करेगा। कांग्रेस के लिए यह एक मौका है कि वह अपनी पुरानी ताकत वापस लाए, लेकिन इसके लिए उसे अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करना होगा।

भितरघात का असर

1 कांग्रेस

कब और क्या हुआ

मध्य प्रदेश (2020) : ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा जॉइन की। उनके साथ 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ी, जिसके कारण कमलनाथ की सरकार गिर गई। यह भितरघात कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 महीने पहले ही बनी सरकार चली गई।

हरियाणा विधानसभा चुनाव (2024) : अक्टूबर 2024 में हुए चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कई उम्मीदवारों ने भितरघात को जिम्मेदार ठहराया। स्थानीय नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम किया, जिससे भाजपा को फायदा हुआ और कांग्रेस सत्ता से बाहर रही।

गुजरात (2017) : विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से लड़ रही थी, लेकिन मणिशंकर अय्यर के 'नीच' बयान ने माहौल बदल दिया। यह भितरघात माना गया, जिसके कारण सत्ता विरोधी लहर का फायदा नहीं मिला और कांग्रेस 77 सीटों पर अटक गई।

नुकसान : सरकार का पतन (मध्य प्रदेश), चुनावी हार (हरियाणा, गुजरात), और संगठनात्मक कमजोरी।



2 भारतीय जनता पार्टी

कब और क्या हुआ

उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव (2024) : जून 2024 में हुए चुनाव में भाजपा की सीटें 62 से घटकर 33 रह गईं। रामपुर, मोहनलालगंज, और श्रावस्ती जैसी सीटों पर उम्मीदवारों ने स्थानीय नेताओं पर भितरघात का आरोप लगाया। इससे वोटों का बंटवारा हुआ और सपा-कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिला।

झारखंड विधानसभा चुनाव (2024) : नवंबर 2024 में भाजपा की हार के बाद नेताओं ने आंतरिक तोड़फोड़ को जिम्मेदार ठहराया। गुटबाजी के कारण पार्टी संगठन कमजोर हुआ और जेएमएम गठबंधन सत्ता में आया।

दमोह उपचुनाव, मध्य प्रदेश (2021) : अप्रैल 2021 में राहुल लोधी की हार के लिए पूर्व मंत्री जयंत मलैया पर भितरघात का आरोप लगा। इससे भाजपा को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

नुकसान : सीटों में भारी कमी (यूपी), सत्ता से बाहर (झारखंड), और स्थानीय स्तर पर हार (दमोह)।

3 शिवसेना

कब और क्या हुआ

महाराष्ट्र (2022) : जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की और 40 विधायकों को साथ लेकर भाजपा संग सरकार बना ली। यह भितरघात शिवसेना के लिए बड़ा झटका था।

नुकसानः पार्टी का विभाजन, सत्ता का नुकसान, और मूल संगठन की कमजोरी।



4 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

कब और क्या हुआ

महाराष्ट्र (2023) : जुलाई 2023 में अजित पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत कर भाजपा-शिवसेना गठबंधन के साथ डिप्टी सीएम बन गए। इससे एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई।

नुकसान : पार्टी का बंटवारा और एनसीपी (शरद पवार) का कमजोर होना।

5 समाजवादी पार्टी

कब और क्या हुआ

लोकसभा चुनाव (2019) : मई 2019 में सपा की हार के बाद आजम खान ने राम गोपाल यादव पर भितरघात का आरोप लगाया। आजम का दावा था कि राम गोपाल ने उन्हें फंसाने के लिए सरकार से साठगांठ की। इससे पार्टी की एकता प्रभावित हुई और केवल 5 सीटें मिलीं।

रामपुर विधानसभा उपचुनाव (2022) : आजम खान के करीबी आसिम रजा की हार के बाद भितरघात की बात उठी। सपा नेताओं के एक धड़े ने भाजपा को फायदा पहुँचाया, जिससे यह सीट हाथ से निकल गई।

नुकसान : चुनावी हार (2019, 2022), और पार्टी में गुटबाजी का बढ़ना।

6 बहुजन समाज पार्टी

कब और क्या हुआ

लोकसभा चुनाव (2024) : मायावती ने अप्रैल 2024 में अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया। आकाश की लोकप्रियता बढ़ रही थी, लेकिन मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बताकर बाहर किया। इसे भितरघात माना गया, जिसके कारण बसपा का युवा वोट बैंक कमजोर हुआ और पार्टी शून्य सीटों पर सिमट गई।

नुकसान : संगठनात्मक कमजोरी और चुनावी प्रदर्शन में गिरावट।

7 आम आदमी पार्टी

कब और क्या हुआ

दिल्ली विधानसभा चुनाव (2025 की कल्पना) : आतिशी ने पार्टी की हार के बाद भितरघात का आरोप लगाया। कहा गया कि कुछ नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम किया, जिससे आप सत्ता से बाहर हुई।

नुकसान : सत्ता से बाहर होना और नेतृत्व पर सवाल उठना।



शिवराज सिंह चौहान या किरेन रिजिजू कौन होगा भाजपा का अगला चीफ !

शारिब जाफरी

नई दिल्ली। राजनतिक हल्कों में आजकल एक ही चर्चा जोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और केरल विधान सभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करने का फैसला किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। वो गुजरात से राज्य सभा साँसद हैं, उन्हें राज्य सभा में नेता सदन के साथ नरेन्द्र मोदी कैबिनेट में स्वास्थ, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में भाजपा की एक पद वाली नीति के तहत ये बात साफ हो गई है, कि अब जेपी नड्डा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। जिसके बाद भाजपा में नए अध्यक्ष को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पार्टी इस बार पिछड़े या दलित चेहरे पर दाँव लगा सकती है। पिछड़ों में सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान का नाम चर्चा में है, जो मध्यप्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और वे संघ के बेहद करीबी हैं। वहीं दलित चेहरों में केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का नाम चर्चा में है। किरेन की गिनती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विश्वासपात्र और उदारवादी नेताओं में होती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से अपना अध्यक्ष बना चुकी है, लेकिन पूर्वोत्तर से अध्यक्ष नहीं बना है। पार्टी ने अगर पूर्वोत्तर से अध्यक्ष लाने का फैसला किया तो किरेन रिजिजू के नाम पर मुहर लग सकती है। किरेन रिजिजू नरेन्द्र मोदी कैबिनेट में संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भाजपा मलिकार्जुन खरगे की काट में किरन रिजिजू के नाम पर विचार कर सकती है।

देश में दलित मतदाता 17 फीसदी हैं, लोक सभा की 543 सीटों में से 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। 173 लोक सभा सीटें ऐसी हैं, जिस पर दलित मतदाता जिसके साथ जुड़ता है, कामयाबी उस के कदम चूम लेती है। 2009 के लोक सभा चुनाव

संघ की चली तो शिवराज ही होंगे अध्यक्ष

शिवराज सिंह चौहान भाजपा के वफादार और संघ के चहेते नेताओं में से एक हैं। सूत्र बताते हैं संघ इन्हें अगले भाजपा अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। वे मध्यप्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री रहे हैं व वर्तमान में केन्द्रीय कृषि मंत्री हैं। उनका जन्म 5 मार्च, 1959 को सीहोर जिले के जैत गांव में किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम प्रेम सिंह चौहान और उनकी मां का नाम सुंदर बाई चौहान है। इनकी जाति किरार है। मध्यप्रदेश में यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। शिवराज भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से एमए दर्शनशास्त्र से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। शिवराज सिंह चौहान छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं। वह 1975 में मॉडल स्कूल स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुने गए थे। 1975-76 में इमरजेंसी के खिलाफ अंडग्राउंड आंदोलन में हिस्सा लिया। 1976-77 में आपातकाल के दौरान वे जेल भी गए। 1977 से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं।

में दलितों के लिए आरक्षित 84 सीटों में से 30 सीटें काँग्रेस ने जीती थीं। 12 सीट भाजपा और 10 सीट सपा जीती थी। जिस का नतीजा ये रहा कि काँग्रेस ने सत्ता में वापसी कर ली। वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव में दलितों के लिए आरक्षित 84 सीटों में भाजपा ने 40 सीट जीत ली। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस रही, जिसने आरक्षित 11 सीट जीती, काँग्रेस को 6 सीटें मिली। 2019 के लोक सभा चुनाव में भाजपा दलितों के लिए आरक्षित 84 सीटों में से 46 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि काँग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिलीं, लेकिन 2024 के लोक सभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए आरक्षित 84 सीटों में सिर्फ 30 सीटों पर सिमट गई। जबकि काँग्रेस 20 सीटें जीतने में कामयाब रही, भाजपा को 2019 के मुकाबले 2024 के लोक सभा चुनाव में जिन 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा उन में से 14 सीटें काँग्रेस जीत गई। जिसका नतीजा ये रहा, की 400 पार का नारा देने वाली भाजपा 240 पर सिमट गई।

भाजपा को एक बार फिर दलित वोटरों को साधने के लिए बौद्ध नेता की जरूरत क्यों पड़ रही हैं, इसका अंदाजा इन आँकड़ों से भी लगाया जा सकता है, 2024 के लोक सभा चुनाव में भाजपा ने दलितों के लिए आरक्षित 84 सीटों में 30 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि काँग्रेस 20 सीटें जीतने में कामयाब रही है। लेकिन असली खेला वोटों के अन्तर में हुआ है, भाजपा 2 लाख 91 हजार के औसत अन्तर से जीती है, तो वहीं काँग्रेस की जीत का औसत अन्तर 3 लाख 17 हजार है। 2019 के चुनाव भाजपा में 46 सीट 2 लाख 3 हजार के औसत अन्तर से जीती थी, तो वहीं काँग्रेस 6 सीट 1 लाख 29 हजार के औसत अन्तर से जीती थी।

राजनीति में दलित वोटरों का महत्व

देश में दलित मतदाताओं के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विपक्ष ने बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के लिखे भारत के संविधान के खतरे का नैरिटिव सेट किया तो 400 पार का नारा देने वाली भाजपा 240 पर सिमट गई। चुनाव में करीब 3 फीसद दलितों का वोट भाजपा से छिटक गया, जबकि 2 फीसदी वोट शेयर सहयोगियों के भी कम हो गए यानि करीब 5 फीसद दलित वोटर भाजपा से दूर हो गया। भाजपा और सहयोगी दलों का जो दलित वोट शेयर खिसका वो सीधे 7 फीसद इण्डिया ब्लाक में जुड़ गया। देश के अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश में 44, पश्चिम बंगाल 29, तमिलनाडु 22, पंजाब 13, कर्नाटक 13, राजस्थान 12, आंध्र प्रदेश 9, बिहार 9, हरियाणा 5, तेलंगाना 3, मध्य प्रदेश 9 और महाराष्ट्र में 6 सीट ऐसी हैं, जहाँ 20 फीसद से ज्यादा दलित वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं।

देश में लोक सभा की 173 सीटें ऐसी हैं, जहाँ दलित वोट निर्णायक भूमिका में हैं। इन 173 सीटों में से विपक्षी गठबंधन ने 112 और एनडीए ने 61 सीटें जीतीं। देश के 74 जिलों में दलित आबादी 25 फीसदी से ज्यादा है, यानि हर चार वोटर में एक दलित वोटर है। लोक सभा चुनाव के नतीजों पर मंथन करने के बाद भाजपा ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जिस का नतीजा महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिला। लोक सभा चुनाव में एनडीए के मुकाबले महाविकास आघाडी को 11 फीसद वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन विधान सभा चुनाव में भाजपा ने ना सिर्फ 11 फीसद वोटों का फासला तय किया बल्कि 7 फीसदी वोटों की बढ़त बना ली।

देश में करीब 20 करोड़ 90 लाख दलित वोटर हैं, जो देश की आबादी का 17 फीसदी हैं, इन में से करीब 77 फीसदी दलित ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जबकि पूरे देश की आबादी के करीब 69 फीसदी लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इन आँकड़ों से जाहिर है, कि ज्यादातर दलित आबादी गांवों में रहती हैं। देश के करीब 23 फीसदी दलित शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि पूरे देश की आबादी के करीब 31 फीसदी लोग शहरी इलाकों में रहते हैं।

एससी के लिए आरक्षित 84 सीटों के अलावा देश में आदिवासियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 2009 के लोक सभा चुनाव में काँग्रेस ने 20 सीटें जीतीं थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 सीटें गई थीं। वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव में मोदी लहर में मामला पलट गया, आरक्षित 47 सीटों में से 27 सीटें भाजपा ने जीत ली, जबकि काँग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। 2019 के लोक सभा चुनाव में भाजपा ने एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटों में 31 सीट जीत ली, जबकि काँग्रेस को सिर्फ 4 सीट मिली, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिलीं, यानि 2019 के मुकाबले भाजपा को 6 सीटों का नुकसान हुआ। इस दौरान 2024 के चुनाव में काँग्रेस को 12 सीटें मिली।

सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे के मुताबिक काँग्रेस को छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में आदिवासी वोटरों ने बढ़त दिलाई, तो वहीं



नार्थ ईस्ट में भाजपा का चेहरा हैं किरेन रिजिजू

किरेन रिजिजू वर्तमान में केन्द्रीय मंत्री है। प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र नेताओं में से एक हैं। उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के नफरा के पास नाखु में रिंचिन खारु और चिरई रिजिजू के घर एक अग्रणी परिवार में हुआ। उनके पिता अरुणाचल के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किरेन रिजिजू को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा माना जाता है। वे अरुणाचल प्रदेश से चौथी बार सांसद चुने गए हैं।

गुजरात में भाजपा और काँग्रेस के बीच 49 - 49 फीसदी वोट दोनों के बीच बंट गए। ऐसा ही झारखण्ड और उत्तराखण्ड में भी हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, कर्नाटक, ओड़ीसा, आंध्रा प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आदिवासी मतदाताओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ था।

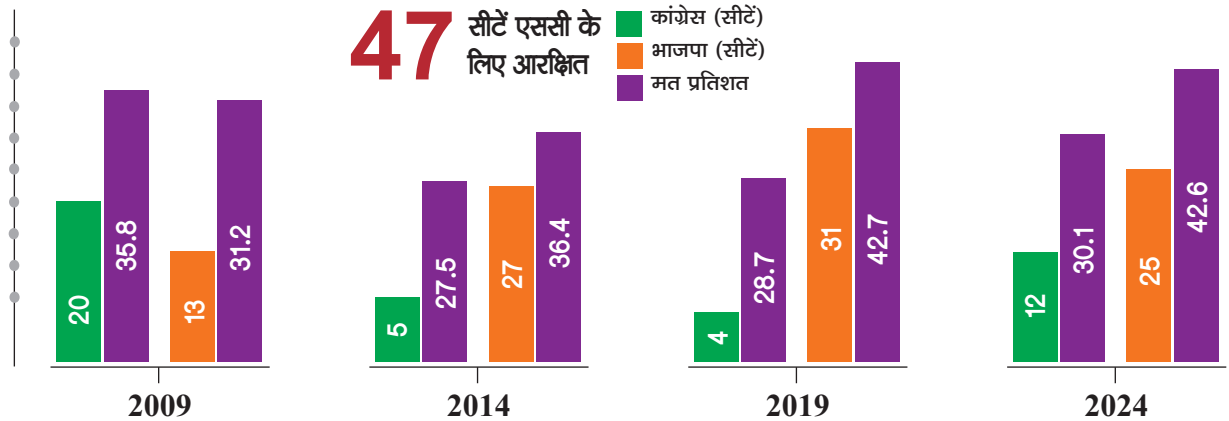
लोक सभा चुनाव 2024 में एससी एसटी के आरक्षित 131 सीटों में से भाजपा को 56 सीटें मिली हैं, काँग्रेस 32 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। 2019 के लोक सभा चुनाव में भाजपा आरक्षित 131 सीटों में से 77 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि काँग्रेस को सिर्फ 10 सीटें मिली थीं। दलित वोटरों का इण्डिया गटबंधन की तरफ झुकाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फैजाबाद लोक सभा की जनरल सीट पर सपा ने एससी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को चुनाव लड़ा दिया और वो जीत हासिल करने में कामयाब रहे, कुछ इसी तरह का खेला मेरठ में भी होते होते बचा, सपा ने दलित चेहरे सुनीता वर्मा पर दाँव लगाया लेकिन वो मामूली अन्तर से चुनाव हार गई।

लोक सभा चुनाव में मिले इन्हीं झटकों से भाजपा ने सबक लेते हुए विपक्ष के सामने नई रणनीति तैयार की है, किरन रिजिजू को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना कर दलित चेहरे को सामने रख पार्टी आगामी चुनावों में जाएगी। इस के लिए किरेन रिजिजू को पिछले कई वर्षों से तैयार किया जा रहा था, वो काँग्रेस नेता राहुल गाँधी के खिलाफ आक्रामक तेवर के साथ सामने आते रहे, पार्टी वक्त बेक्त उनका चेहरा आगे कर बचाव करती नजर आई। महाकुम्भ 2025 में वो त्रिवेणी में डुबकी लगाते भी नजर आए।

संक्षिप्त जानकारी

- शिवराज सिंह चौहान संघ के विश्वासपात्र हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है।
- वह चार बार मप्र. के मुख्यमंत्री रहे और अब केन्द्र में मंत्री हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं।
- देश में विपक्ष बार-बार पीडीए का नारा देकर भाजपा को अगड़ों के साथ खड़ी पार्टी दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे में एक पिछड़े को अध्यक्ष बनाकर भाजपा एक तीर से कई निशाने साध सकती है।
- बिहार, तमिलनाडु व अन्य राज्यों के आगामी चुनाव में भाजपा को लाभ मिल सकता है, इससे पिछड़ों में अच्छा संदेश जाएगा।
- शिवराज के लम्बे राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी को मिल सकता है, जिससे संगठन को मजबूत करने में आसानी होगी।
- किरेन रिजिजू को पीएम नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का विश्वासपात्र माना जाता है।
- किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं व केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं।
- लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान किरेन रिजिजू ने खुद को भीम राव आम्बेडकर का वारिस बताते हुए कहा कि मैं केन्द्र में पहला बौद्ध मंत्री हूँ।
- कांग्रेस ने दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बना रखा है, ऐसे में किरेन रिजिजू का चेहरा उनकी काट के तौर पर अध्यक्ष बनाकर पेश किया जा सकता है।
- किरेन रिजिजू का भी लम्बा राजनीतिक अनुभव है। वे 2004, 2014, 2019 और 2024 में अरुणाचल से सांसद चुने गए हैं।

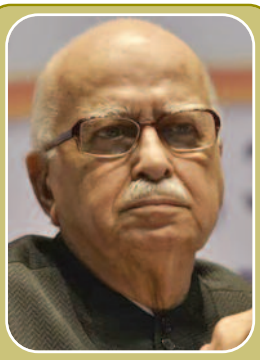
सीटें और मत प्रतिशत



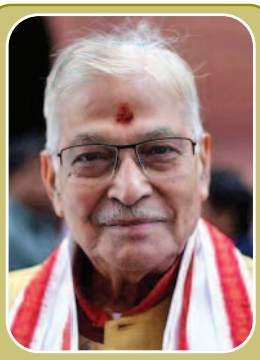
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष



अटल बिहारी बाजपाई
1980 - 1986



लाल कृष्ण आडवाणी
1986 - 1990, 1993-1998, 2004 -2005



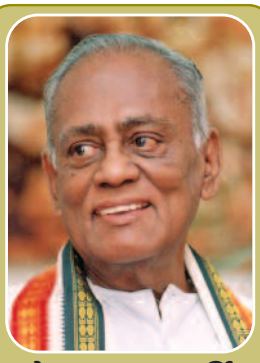
मुरली मनोहर जोशी
1991 - 1993



कुशभाऊ ठाकरे
1998 - 2000



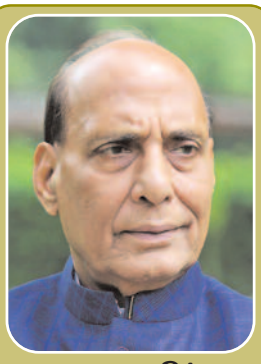
बंगारु लक्ष्मण
2000 - 2001



के जना कृष्णमूर्ति
2001 - 2002



एम वैंकैया नायडू
2002 - 2004



राजनाथ सिंह
2005 - 2009
2013 - 2014



नितिन गडकरी
2010 - 2013



अमित शाह
2014 - 2017
2017 - 2020



जगत प्रकाश नड्डा
2020 से वर्तमान में



परिसीमन को लेकर उत्तर और दक्षिण आमने-सामने

- केन्द्र में संख्या बल को लेकर चिंतित दक्षिण के राज्य
- तमिलनाडु में चुनाव से पहले शह और मात का खेल



तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन कहते हैं, कि हमारी मांग है कि आबादी में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के उपायों को गंभीरता से अपनाने के लिए दक्षिणी राज्यों को लोकसभा सीटें कम कर दंडित न किया जाए।



केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि स्टालिन महोदय, नरेन्द्र मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, कि परिसीमन के बाद आनुपातिक आधार पर किसी भी दक्षिणी राज्य में एक भी सीट नहीं घटेगी।

सैय्यद कासिम

नई दिल्ली। देश में वर्ष 2026 में नए सिरे से परिसीमन की कवायद से पहले ही दक्षिण राज्यों में बेचैनी साफ नजर आने लगी है, 1976 में इन्दिरा गाँधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी थी।

इस रोक के पीछे सरकार का मकसद जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को बढ़ावा देना था, सरकार की चिंता की सब से बड़ी वजह ये थी, कि ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को ज्यादा सीटें हासिल हो जाएंगी। ये उन राज्यों की कीमत पर होगा जो अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण रखने में सफल रहे। उत्तर और दक्षिण के राज्यों में संभावित असंतुलन को रोकने के लिए फैसला लिया गया था, कि सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर ही बना रहेगा। शुरु में रोक 2001 तक लागू रहनी थी, लेकिन 2002 में 84वें संविधान संशोधन के जरिए इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया। अब जैसे जैसे नए परिसीमन की तारीख करीब आ रही है, दक्षिण के राज्य अपनी राजनैतिक आवाज, संघीय स्वायत्तता और आर्थिक योगदान सुरक्षित रखने की खातिर परिसीमन की कवायद के खिलाफ उठ खड़े होने और जंग का ऐलान कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री एम.के. स्टालिन ने 5 मार्च 2025 को बैठक बुलाई, जिसमें राज्य के सभी नेताओं ने आगे होने वाली परिसीमन की कवायद को अपनी राजनैतिक प्रासंगिकता पर हमला करार दिया और इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। एम के स्टालिन ने आगाह किया कि अगर आबादी के कच्चे आँकड़ों के आधार पर परिसीमन किया गया, तो इस मंसूबे के तहत अपनी जन्म दरों पर नियंत्रण रखने वाले दक्षिणी राज्यों को सजा दी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं करने वाले उत्तर के राज्यों को इनाम से नवाजा जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमन्त्री सिद्धरामैया, तेलंगाना

के मुख्यमन्त्री अनुमुला रेवंत रेड्डी और केरल के मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन ने भी ऐसी ही आशंकाएं जाहिर करते हुए आगाह किया, कि संसद में दक्षिण की कम मौजूदगी का मतलब यह होगा कि उन्हें केन्द्रीय धन के आवंटन में कमी आएगी और देश के दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक गैर बराबरी और गहरी हो जाएगी। ऐसे में उत्तर भारत के राज्य पहले से ही प्रतिनिधित्व कम होने का रोना रो रहे थे, अब दक्षिण भारत के राज्य भी अब फिक्र की एक मोटी लकीर खींच रहा है।

महज आबादी के आधार पर पुनर्गठन का मतलब यह होगा कि खालिस अपनी तादाद के बूते उत्तरी राज्य राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगे। दक्षिणी राज्यों का मानना है, कि इससे देश का संघीय संतुलन बदल जाएगा और उनके लिए अहम नीतिगत मामलों में अपने हितों की रक्षा करना और मुश्किल हो जाएगा। परिसीमन का मुद्दा कितना गम्भीर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि भाजपा के सहयोगी आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबू नायडू भी बेचैन नजर आ रहे हैं, वो पहले ही कह चुके हैं, की अपना असर बनाए रखने के लिए दक्षिण के राज्य जनसंख्या नीति पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो सकते हैं।

तमिलनाडु में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर परिसीमन का विरोध किया जा रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनैतिक दल इसे भेदभावपूर्ण कदम मान रहे है, जो संविधान की संघीय भावना को खोखला कर देगा। तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री एम के स्टालिन परिसीमन को प्रदेश की स्वायत्तता पर अतिक्रमण करने के इरादे से केन्द्र के ज्यादा बड़े पैटर्न के हिस्से के तौर पर देखते हैं, उन्होंने केन्द्र सरकार पर बार-बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी और राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा एनईईटी / नीट सरीखी नीतियों के जरिए राज्य की वित्तीय और शैक्षिक स्वायत्तता को कमजोर करने का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि संसदीय सीटों में कमी से यह रुझान और तेज होगा, जिससे लोकसभा में अपने हितों की वकालत करने के लिए तमिलनाडु के पास नुमाइंदगी करने वालों की तादाद और कम हो जाएगी। स्टालिन ने आगाह किया है कि दक्षिणी के राज्यों के सिर पर तलवार लटक रही है।

कर्नाटक में कॉंग्रेस की सरकार है, मुख्यमन्त्री सिद्धरामैया का दावा है, कि केन्द्र सरकार के कदम लगातार राज्य को सजा दे रहे हैं, चाहे वह कर राजस्व वितरण में हेर-फेर हो, जीएसटी और आपदा राहत में असमानताएं हों, दबंगई से लागू शिक्षा नीति हो, या यूजीसी यानि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मनमाने फेरबदल हों। वो कहते हैं, परिसीमन संसद में दक्षिण की नुमाइंदगी को कमजोर करने और केन्द्र की नाइंसाफियों को चुनौती देने की हमारी क्षमता का गला घोंटने की एक और कोशिश है। तेलंगाना के मुख्यमन्त्री रेवंत रेड्डी इस मामले पर और भी ज्यादा मुखर हैं, रेवन्त रेड्डी कहते हैं, कि भाजपा परिसीमन का इस्तेमाल दक्षिण को दरकिनार करके बीमारू राज्यों की सीटें बढ़ाकर पिछले दरवाजे से अपना दबदबा मजबूत करने की रणनीति के तौर पर कर रही है। चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, कि परिसीमन के बलबूते उत्तर भारत में दबदबा रखने वाली भाजपा सरीखी पार्टियां नए गढ़ स्थापित कर सकती हैं। कर्नाटक के मुख्यमन्त्री सिद्धरामैया कहते हैं, कि नरेन्द्र मोदी सरकार के असाधारण उत्साह को देखते हुए लगता है, कि भाजपा का इरादा दक्षिण के लोगों को भाजपा का विरोध करने की सजा देना है।

दरअसल नारी शक्ति वन्दन विधेयक पास हो जाने के बाद उस को अमल मे लाने के लिए परिसीमन

आंकड़ों पर नजर

बढ़े लाभार्थी

देश की आबादी में 39 फीसद हिस्सेदारी और 2 से अधिक प्रजनन दर वाले चार उत्तर भारतीय राज्यों में 31 लोकसभा सीटों के इजाफे का अनुमान है। कुल सीटों में उनका प्रतिनिधित्व 32 फीसद से बढ़कर 38 फीसद हो जाएगा और सीटें 205 हो जाएंगी। ये राज्य फिलहाल देश की जीडीपी में 24 फीसद का योगदान करते हैं। अगर कुल सीटें 848 तक बढ़ा दी जाएं, तो इन प्रदेशों में 150 सीटें बढ़ जाएंगी, जो औसत राष्ट्रीय 56 फीसद बढ़ोतरी के मुकाबले 86 फीसद का इजाफा होगा।

उत्तर प्रदेश
प्र.द. : 2.4% जीडीपी शेयर : 8.4%
199,812,341
80 91 (+11) 143 (+63)

बिहार
प्र.द. : 3% जीडीपी शेयर : 4.3%
13,07,25,310
40 50 (+10) 79 (+39)

राजस्थान
प्र.द. : 2% जीडीपी शेयर : 5%
68,548,437
25 31 (+6) 50 (+25)

मध्य प्रदेश
प्र.द. : 2% जीडीपी शेयर : 6.1%
7,26,26,809
29 33 (+4) 52 (+23)

कुल आबादी
मौजूदा लोकसभा सीटें
2026 की अनुमानित सीटें
नई लोकसभा की कुल सीटों के हिसाब से

बड़े नुक्सान वाले

देश की आबादी में 21 फीसद हिस्सेदारी और जीडीपी में फिलहाल 31 फीसद योगदान देने वाले पांच दक्षिण भारतीय राज्यों को कमतर प्रजनन दर 1.8 या उससे कम की वजह से 26 लोकसभा सीटों का घाटा होगा। कुल लोकसभा सीटों में उनका प्रतिनिधित्व 24 फीसद से घटकर 19 फीसद हो जाएगा और उनके पास 103 सीटें ही रह जाएंगी। अगर सीटें 848 तक बढ़ा दी जाती हैं, तो उन्हें 35 सीटों का फायदा होगा, जो कुल लोकसभा सीटों में 56 फीसद बढ़ोतरी के मुकाबले महज 27 फीसद इजाफा होगा।

कर्नाटक
प्र.द. : 1.7% जीडीपी शेयर : 8.2%
6,10,95,297
28 26 (-2) 41 (+13)

तेलंगाना
प्र.द. : 1.8% जीडीपी शेयर : 4.9%
3,50,03,674
17

आंध्र प्रदेश
प्र.द. : 1.7% जीडीपी शेयर : 4.7%
4,95,77,103
25 34 (-8) 54 (+12)

तमिलनाडु
प्र.द. : 1.8% जीडीपी शेयर : 8.9%
7,21,47,030
39 31 (-8) 49 (+10)

केरल
प्र.द. : 1.8% जीडीपी शेयर : 3.8%
3,34,06,061
20 12 (-8) 20 (0)

उत्तर चाहता है, परिसीमन दक्षिण नहीं आखिर क्यों?

- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों ने आबादी बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब उनके सामने संसदीय सीटें खोने का खतरा है, क्योंकि उनका नए सिरे से आवंटन आबादी के आधार पर होना है। परिसीमन से उच्च आबादी वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ने से उनका राजनैतिक रसूख घट सकता है।

- उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भारी आबादी बढ़ोतरी देखी गई है, मगर सांसदों की संख्या 1971 के हिसाब से ही बनी हुई है, जिससे प्रतिनिधित्व में भारी कमी है।



- दक्षिण भारतीय नेताओं की दलील है कि अगर लोकसभा सीटों का नए सिरे से आवंटन आबादी के आधार पर किया जाता है तो समान प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा का पुनर्गठन होना चाहिए, जिसमें आबादी का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए।

- दक्षिण भारतीय नेताओं की दलील है कि अगर लोकसभा सीटों का नए सिरे से आवंटन आबादी के आधार पर किया जाता है तो समान प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा का पुनर्गठन होना चाहिए, जिसमें आबादी का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए।

- दक्षिणी राज्य देश की जीडीपी और कर राजस्व में काफी योगदान करते हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी संख्या घट सकती है। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच आर्थिक गैर बराबरी काफी बढ़ रही है। परिसीमन से यह खाई और चौड़ी हो सकती है।

- उत्तरी राज्यों की दलील है, कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के संवैधानिक सिद्धांत को ध्यान में रखकर प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से होना ही चाहिए। फिलहाल दक्षिण भारत में प्रति सांसद मतदाताओं का प्रतिनिधित्व उत्तरी राज्यों के मुकाबले ज्यादा है।

से जोड़ने का कदम राजनैतिक अहमियत रखता है, महिलाओं की संसद में 33 फीसदी भागीदारी के मकसद से पास कराए गए महिला आरक्षण विधेयक को निर्वाचन क्षेत्रों की नई लकीरें खींचने पर निर्भर बनाकर सरकार ने न सिर्फ परिसीमन को जरूरी बना दिया, बल्कि बहस को नए सांचे में ढाल कर विवादास्पद चुनावी परिसीमन को स्त्री पुरुष न्याय के रूप में परोसा जा रहा है। सरकार की दोहरे उद्देश्य वाली रणनीति से विपक्षी दल खासकर दक्षिण राज्यों के विपक्षी दल दबाव में हैं, कि महिलाओं के आरक्षण को संवैधानिक जरूरतों से बांधकर उसमें देरी करने की आलोचना से बचते हुए परिसीमन को कैसे स्वीकार करें।

परिसीमन की कवायद के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन पर भी फर्क पड़ेगा।

दक्षिण के राज्यों में सबसे ज्यादा मुखर तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री एम के स्टालिन हैं, तमिलनाडु में अगले वर्ष चुनाव होना है, ऐसे में मोर्चा केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह ने संभाला है, उन्होंने एम के स्टालिन को जवाब देते हुए कहा कि तमिलनाडु की एक भी सीट कम नहीं होगी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिणी के राज्यों को भरोसा दिलाया है, कि उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलै ने कहा कि राज्य में लोगों के बीच ऐसा डर पैदा करने की कोशिश हो रही है, जो काल्पनिक है, उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए स्टालिन की तीखी आलोचना की है। दक्षिणी के राज्यों के नेताओं की चेतावनी और भाजपा के रुख के बीच परिसीमन नए राजनैतिक अखाड़े का रूप ले चुका है।

क्या है परिसीमन

देश में परिसीमन की कवायद संविधान के तहत होती है, आबादी में आए बदलावों को आधार बना वक्त वक्त पर संसदीय और राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन होता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक, हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधान सभाओं की सीटों का आवंटन इस तरह किया जाना चाहिए, जिससे आनुपातिक प्रतिनिधित्व तय हो सके। इसी तरह अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की सीटों के बंटवारे का प्रावधान है। परिसीमन की प्रक्रिया आयोग पूरी करता है, आयोग के पास आबादी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तैयार करने और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें तय करने का अधिकार है।

आजादी के बाद देश में परिसीमन की चार बड़ी कवायदें की गईं। पहली 1952 फिर 1963 और 1973 में की गईं। परिसीमन की ये कवायदें 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद की गईं थीं।

कवायद में जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या तय की गई। जिस की वजह से लोकसभा की सीटों की संख्या 494 से बढ़ कर 522 और आखिरकार 1971 के बाद 543 हो गई। इस कवायद में निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं खींची गई ताकि तमाम राज्यों को प्रति मतदाता बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके, लेकिन 1976 में इन्दिरा गाँधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी। इसके पीछे तर्क जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को बढ़ावा देना था, सरकार के सामने बढ़ती चिंता का सबब यह था, कि ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों खास कर उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी और यह उन राज्यों की कीमत पर होगा जो अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण रखने में कामयाब रहे। इस कथित असंतुलन को रोकने के लिए फैसला लिया गया कि सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर ही बना रहेगा। पहले यह रोक 2001 तक लागू रहनी थी, लेकिन वर्ष 2002 में एनडीए की अटल बिहारी बाजपाई सरकार ने 84वें संविधान संशोधन के जरिए इसे 2026 तक बढ़ा दिया। जिस की वजह से 2002 की परिसीमन की कवायद 2001 की राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं जनगणना के आँकड़ों के आधार पर नए सिरे से खींचने और हर राज्य में जनसंख्या के वितरण के अनुरूप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण में सुधार करने तक सीमित थी।

अब सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक वर्ष 2026 की समय सीमा नजदीक आ रही है, तो देश के सामने परिसीमन की पूर्ण कवायद को अंजाम देने की चुनौती है। ये कवायद जनगणना 2021 के आधार पर होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण टल गई, और जनगणना की कवायद शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये भी उठना लाजमी है, कि परिसीमन का पुनर्निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा।

आखिर दक्षिण के राज्य पसोपेश में क्यों

देश के नए संसद भवन में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, इसलिए नए परिसीमन के बाद सीटों में वृद्धि की संभावना है, जिससे यह तय होगा कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व पूरी तरह खत्म न हो। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत आबादी में बदलाव के मुताबिक हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाना है, लेकिन अनुच्छेद 81 में 550 सीटों की सीमा तय की गई है, जिस में 530 राज्यों के लिए और 20 केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए। ऐसे में सीटों की कुल संख्या बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 81 में बदलाव करना होगा।

देश में नए परिसीमन की कवायद से उत्तर और दक्षिण के राज्यों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व में बड़ा बदलाव आ सकता है। लोकसभा सीटों की संख्या अगर 543 बनी रहती है, तो उत्तरी राज्यों उत्तर प्रदेश,



बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 31 सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि दक्षिणी के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्रा प्रदेश को 26 सीटें खोनी पड़ेंगी। सीटों में बदलाव उत्तर की उच्च जनसंख्या वृद्धि और उच्च प्रजनन दर के कारण है, ऐसे में नीतिगत प्राथमिकताओं में असंतुलन पैदा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

लोकसभा सीटों की संख्या अगर 848 तक बढ़ा दी जाए, तो बदलाव और बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अतिरिक्त 150 सीटें मिलेंगी, जबकि दक्षिण के पांच राज्यों को सिर्फ 35 सीटों का लाभ होगा। ऐसा अनुमान वर्ष 2019 के एक अध्ययन की गणना के मुताबिक लगाया गया है। इस तरह उत्तर को हासिल सीटों का लाभ राष्ट्रीय निर्णय में दक्षिण के असर को और कम करेगा। बस दक्षिण के राज्यों पर यही असंतुलन माथे पर शिकन की वजह है। उत्तर भारत का सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 24 फीसद का योगदान है, जबकि दक्षिण राज्यों का जीडीपी में 31 फीसद का योगदान है। आर्थिक योगदान के अनुपात को ध्यान में रखे बिना प्रतिनिधित्व में बदलाव राजकोषीय संघवाद में तनाव बढ़ा सकता है। बीआरएस के अध्यक्ष के.टी. रामराव का कहना है, कि परिसीमन में राज्यों के वित्तीय योगदान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन का मानना है, कि तेलंगाना की आबादी देश की आबादी का 2.8 फीसद है, लेकिन जीडीपी में योगदान 5.2 फीसद है।

द्रमुक का परिसीमन विवाद पर फोकस तमिलनाडु चुनावों के पहले शुरुआती रणनीतिक चाल भी हो सकती हैं, चुनाव महज साल भर दूर हैं।

दक्षिणी के राज्य पहले ही राष्ट्रीय वित्त आवंटन में कमतर हिस्सेदारी महसूस करते हैं। उनकी दलील है, कि प्रतिनिधित्व में सिर्फ आबादी का ही नहीं, बल्कि आर्थिक उत्पादन, कर योगदान और विकास संकेतकों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इसका दूसरा पहलू यह है कि परिसीमन पर सीमा अनुच्छेद 81 के तहत निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का खंडन है, जिसके मुताबिक हर लोकसभा सांसद को 5 लाख से लेकर 7 लाख 50 हजार लोगों का प्रतिनिधि होना चाहिए, लेकिन 1976 से सीट पुनर्वितरण पर संवैधानिक रोक की वजह से हर निर्वाचन क्षेत्र की औसत आबादी में काफी वृद्धि हुई है, अब कुछ सांसद लगभग 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर साँसद के लिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पर विचार करने पर परिसीमन का असर और अधिक गहरा हो जाता है।

उत्तरी राज्यों में 18 वर्ष से कम आयु वालों की आबादी ज्यादा है, और इसलिए उनकी कुल आबादी के मुकाबले हर निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं का अनुपात कम है। उत्तर प्रदेश में एक साँसद लगभग 31 लाख लोगों का प्रतिनिधि है, जबकि तमिलनाडु में एक साँसद 19 लाख 80 हजार लोगों का प्रतिनिधि है, लेकिन रजिस्टर्ड वोटरों के मामले में फर्क सिर्फ 3 लाख का है। कई आलोचकों का मानना है, कि परिसीमन की सीमा से एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत कमजोर हो गया है। परिसीमन की कवायद संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन में भी ब?ा फर्क लाएगी। इन सीटों का आरक्षण हर राज्य में उनकी आबादी के अनुपात में होती हैं, इसलिए उच्च

वृद्धि दर वाले राज्य, खासकर उत्तर में, अधिक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बढ़ सकते हैं, जबकि कम आबादी वृद्धि वाले दक्षिणी राज्यों को आरक्षित सीट खोना पड़ सकती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुमानों के मुताबिक, देश में अनुसूचित जाति आरक्षित दो सीट और अनुसूचित जनजाति आरक्षित एक सीट बढ़ सकती है, इस के अलावा 18 निर्वाचन क्षेत्रों में उनके आरक्षण की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे सीटें खोने वाले राज्यों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राजनैतिक रसूख को कम कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय नेताओं का विरोध भी देखने को मिल सकता है।

चिंताएं और भी हैं

तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री एम के स्टालिन इसे परिसीमन से कहीं आगे, अधिकारों की लड़ाई तक ले जाने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। अपने जन्मदिन 1 मार्च 2025 को उन्होंने घोषणा की, हम देश में भाषा की लड़ाई की दिशा तय करने वालों में अग्रणी रहे हैं। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत तीन-भाषा नीति को हिन्दी थोपने की कोशिश करार देते हैं और इसे केन्द्र के अतिक्रमण से जुड़ा एक और पहलू करार देते हैं, जो पहले से ही तमिलनाडु को उसके हिस्से की धनराशि से वंचित कर रहा है। परिसीमन और एनईपी की भाषा नीति के मुद्दे से उत्तर दक्षिण विभाजन के गहराने का खतरा भी बढ़ जाता है।

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है, की तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री एम के स्टालिन का आक्रामक अभियान किस रूप में सामने आएगा। इस नजरिये से क्रिस्टोफ जफरले की अगुआई में विश्लेषकों के अध्ययन को अहम माना जा सकता है, पेरिस स्थित इंस्टीट्यूट मोंटेन से प्रकाशित अध्ययन भारत विरोधाभासी क्षेत्रीय गतिशीलता की चुनौती में देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और सामाजिक कल्याण के मामले में गहरी क्षेत्रीय गैर बराबरी का जिक्र किया गया है। इससे पता चलता है, कि बहस दो मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित होगी।

पहला, उत्तर दक्षिण के बीच बढ़ती खाई तनाव बढ़ाएगी। दूसरा, नरेन्द्र मोदी के गुजरात मॉडल पर आधारित आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल उठेंगे। इसके उलट, तमिलनाडु का वैकल्पिक नजरिया समावेश और मानव विकास का है। बेरोजगारी और निम्न मध्य वर्ग की तेजी से हालत खराब होने से तमिलनाडु की सफलता की कहानी लोगों का ध्यान खींच सकती है, जो गुजरात मॉडल को चुनौती दे सकती है, जो संघवाद के नाम पर विविध क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट करने की स्टालिन की क्षमता उनकी स्थिति को मजबूत कर सकती है।

चुनावी मुद्दा

राजनैतिक विश्लेषक परिसीमन पर बहस को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले द्रमुक की रणनीतिक चाल मान रहे हैं, जिसमें अब एक साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में ये भाजपा की अगुआई वाली केन्द्र सरकार की तरफ से एनईपी से जुड़ी फंडिंग, त्रिभाषा फॉर्मूला और नीट यानि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा जैसे मुद्दों के जरिए व्यापक राजनैतिक नैरेटिव से भी जुड़ता है। सर्वदलीय बैठक कर एम के स्टालिन ने जता दिया है, कि यह राज्य के अधिकारों और तमिल पहचान का मसला है।

भाजपा ने द्रमुक को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। दरअसल तमिल युवाओं की नई पीढ़ी द्रमुक और अन्नाद्रमुक को स्थिर सरकारों के तौर पर देखती है, जो समाज कल्याण की योजनाएं लागू करती रही हैं। इस वैचारिक लड़ाई में द्रमुक लाभ की स्थिति में रही है, क्योंकि हिंदुत्व और अन्नाद्रमुक के भाजपा के साथ जुड़ाव को मुद्दा बनाकर ही एम के स्टालिन के नेतृत्व में पार्टी ने लगातार तीन चुनाव जीते हैं, वर्ष 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव और 2021 का विधानसभा चुनाव। और अब भाजपा ने एम के स्टालिन को एक और मुद्दा थमा दिया, जो केन्द्र और राज्य के संबंधों और सामाजिक न्याय के साथ ही द्रविड़ मॉडल से भी जुड़ा है।

इन हालात में परिसीमन पर बहस जैसे हैसे जोर पकड़ रही है, साफ होता जा रहा है कि दक्षिण का प्रतिरोध सिर्फ संख्या बल को लेकर नहीं है, बल्कि वह इसे अपनी राजनैतिक आवाज, आर्थिक योगदान और संघीय स्वायत्तता से जोड़कर देख रहा है। निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से निर्धारण से पहले बहुप्रतीक्षित जनगणना की जरूरत होगी। जनगणना पूरी होने की कोई आधिकारिक समय सीमा न होने के कारण परिसीमन प्रक्रिया शुरू होना अभी सिर्फ अटकलबाजी है। हालांकि, तब तक इसे लेकर बयानबाजियां राजनैतिक चिंगारी को हवा देकर चुनावी रणनीति की दशा और दिशा तय होती रहेगी।

गैर-बराबर प्रतिनिधित्व

मतदाताओं का पंजीकरण हमेशा किसी क्षेत्र की आबादी के आकार से मेल नहीं खाता। उत्तरी राज्यों में 18 वर्ष से कम उम्र की आबादी का अनुपात ज्यादा है, इसलिए मतदाता पंजीकरण दर कम है, जबकि दक्षिणी राज्यों में अधिक राजनैतिक जुड़ाव दिखता है। इससे प्रतिनिधित्व में गैर बराबरी पैदा होती है। उत्तर प्रदेश में एक सांसद औसतन 31 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है, जबकि तमिलनाडु में करीब 20 लाख लोगों का औसत है, जिससे 11 लाख का फर्क हो जाता है। हालांकि, प्रति क्षेत्र मतदाता पंजीकरण में महज 3 लाख का फर्क है।



उत्तरी राज्य

उत्तर प्रदेश	19/31
बिहार	19/32
राजस्थान	21/33
मध्य प्रदेश	19/31

दक्षिण राज्य

तमिलनाडु	16/19.8
केरल	14/18
आंध्र प्रदेश	16/21
तेलंगाना	19/23
कर्नाटक	19/24

(सभी आँकड़े लाख में)

हर सांसद को वोट देने वाले वोटर
हर सांसद का जनसंख्या प्रतिनिधित्व

स्रोत - टेक्निकल ग्रुप आन पापुलेशन प्रोजेक्शनस 2024-2025 की रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग।

अब्दुल्लाह जेल से बाहर आजम की मुश्किलें बरकरार

एस. डब्ल्यू. असगर

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक मोहम्मद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम करीब 16 माह बाद जेल से रिहा हो गए। रामपुर से पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम की एक झलक पाने के लिए हरदोई जेल के बाहर सुबह से ही उनके समर्थक पहुँचने लगे थे। अब्दुल्लाह आजम के जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। समर्थकों के बीच घिरे अब्दुल्ला आजम को को पुलिस ने काफी मशक्कत कर कार में बैठाया, रास्ते भर उनके स्वागत के लिए उनके समर्थक जगह-जगह सड़क किनारे मौजूद थे, सुबह जेल से रिहाई के बाद वो शाम को रामपुर अपने घर पहुंचे। अब्दुल्लाह आजम की रिहाई के बाद मोहम्मद आजम खान के समर्थकों को उम्मीद है, की अब उनको भी जल्द इन्साफ मिलेगा, और वो भी जेल से बाहर आ जाएंगें। गौरतलब है, की देश की सब से बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम खान को शर्तों के साथ शत्रु सम्पत्ति मामले में 17 फरवरी को जमानत दे दी थी।

अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मुकदमे में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 18 अक्तूबर 2023 को मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी तनजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7-7 कैद की सजा सुनाई थी। तनजीम फातिमा जमानत मिल जाने की वजह से पहले ही जेल से रिहा हो गई थी। अब अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों में जमानत मिल जाने के बाद रामपुर की कोर्ट से उनकी रिहाई का परवाना हरदोई जेल भेजा गया था। तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अब्दुल्ला आजम को को हरदोई की जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहाई के बाद उनके बाहर निकलते ही समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। अब्दुल्लाह आजम ने भी कार पर सवार होते वक्त समर्थकों का अभिवादन किया। हरदोई से लेकर रामपुर तक उनके स्वागत के लिए जगह जगह समर्थक फूल मालाओं के साथ मौजूद थे, सुबह करीब 11:40 बजे उन का काफिला हरदोई जेल से रवाना हुआ, जो देर शाम रामपुर पहुँचा, जहाँ उन के आवास के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने उनका स्वागत किया।

जगह-जगह खड़े रहे समर्थक

अब्दुल्ला आजम की रिहाई के मद्देनजर सुरक्षा के भी सख्त इंतेजाम किए गए थे। उन के समर्थकों को भी भारी पुलिस



बल की मौजूदगी का एहसास था। रामपुर से करीब 100 चौपहिया वाहनों से उन समर्थक रवाना हरदोई के लिए रवाना हुए थे। इनमें से लगभग 20 ही हरदोई शहर में आए। बाकी वाहनों को समर्थकों ने शाहजहांपुर रोड पर खड़ा करा दिया, तो कुछ शाहाबाद में भी रुक गए।

आजम खान परिवार को मिली राहत

शत्रु सम्पत्ति की जमीन के रिकार्ड में हेराफेरी के मामले में सपा नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी तनजीम फातिमा और बड़े बेटे अदीब आजम खान और उनकी बहन निकहत अखलाक की रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई। अदालत ने इन सभी की अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है। शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में रिकार्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में हेराफेरी करने का आरोप है। दरअसल, ये मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर परिसर के अंतर्गत आने वाली भूमि का है, जो कि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी वर्ष 1947- 48 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और यह सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति के रूप में वर्ष 2006 में भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग के अंतर्गत दर्ज कर ली थी।



मोहम्मद आजम खान भी जेल से बाहर आएंगें : अखिलेश



अब्दुल्लाह अजम की रिहाई के बाद अब मोहम्मद आजम खान के समर्थक उन की भी रिहाई की उम्मीद में हैं, अब्दुल्लाह आजम खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, कि सरकार समाजवादियों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जेल भेजे गए सभी समाजवादी नेता जल्द ही बरी होंगें। सरकार ने झूठे मुकदमों में सपा नेताओं को जेल भेजा है। अखिलेश यादव ने कहा अब्दुल्ला आजम खान को जमानत मिल गई है, जल्द ही मोहम्मद आजम खान भी जेल से बाहर आएंगें। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को भी सरकार ने झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री समाजवाद का मायने नहीं जानते हैं, समाजवादी कभी झुकता नहीं है।

रिकॉर्ड की जांच करने पर राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जालसाजी कर शत्रु सम्पत्ति को हेराफेरी करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था, और रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए थे। इस मामले में इंवेस्टिगेशन के बाद सपा नेता मोहम्मद आजम खान, उन की पत्नी तनजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह आजम खान, अदीब आजम खान, उन की बहन बहन निकहत अखलाक समेत ट्रस्ट के पदाधिकारियों को धारा 281, 420, 467, 468 व 471 के तहत आरोपी बनाया गया था। इस मामले में मोहम्मद आजम खान की पत्नी तनजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निकहत अखलाक को कोर्ट ने सोमवार तक की अंतरिम जमानत दी थी। 5 मार्च 2025 तीनों एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में हाजिर हुए। अब्दुल्लाह आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिल गई है। अब मोहम्मद आजम खान के समर्थकों को उम्मीद है, जल्दी ही उन्हे भी जमानत मिल जाएगी। मोहम्मद आजम खान के समर्थकों का दावा है, की रिहाई के बाद वो नए तेवर और कलेवर में नजर आएंगें।



राजनीतिक और पारिवारिक मझधार में फंसीं मायावती!

राजेंद्र कुमार

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। यह पहला मौका है, जब मायावती पार्टी की राजनीतिक और पारिवारिक मझधार में फंसी हैं। बीते 30 वर्षों में मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अर्श से फर्श के कई दौर देखे हैं. ऐसे ही उतार चढ़ाव के राजनीतिक माहौल में दलित एकजुटता से शुरू हुई मायावती की राजनीति आगे बढ़ते हुए बहुजन गोलबंदी से होते हुए सर्वजन तक सफल ढंग से फैलती गई। किंतु अब इसमें ठहराव आ गया है. सब देख रहे हैं कि अब सर्वजन को जोड़ने के उनके प्रयास अब दलित आधार मत बचाने की जद्दोजहद तक सिमट गए हैं।

ऐसी परिस्थितियों में मायावती द्वारा लिए गए फैसले भी अब उन्हे मझधार में फंसा रहे हैं। ऐसा ही एक फैसला उन्होने गत दिनों अपने भतीजे आकाश

भतीजे आकाश से उठा माया का भरोसा, सभी पदों से हटाया, पार्टी से भी निकाला

आनंद को पार्टी के प्रमुख पदों से बेदर्दी से हटाने का लिया। इसके बाद आकाश आनंद ने अपनी सफाई दी तो मायावती ने गत 3 मार्च को आकाश आनंद को पार्टी से ही निष्कासन कर हलचल मचा दी। मायावती का कहना है कि आकाश को इसलिए हटाया गया क्योंकि वह अपने ससुर और पूर्व बसपा सांसद अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में थे, जिन्हें पिछले महीने पार्टी से निकाल दिया गया था। आकाश को पार्टी के प्रमुख पदों से हटाए जाने पर पश्चाताप करके परिपक्वता दिखानी चाहिए थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में कद्दावर नेताओं का पार्टी से बाहर होना कोई नई बात नहीं है। मायावती के गुस्से का शिकार होकर तमाम कद्दावर नेता एक झटके में बसपा से निकले गए। जो नेता बसपा में कभी नीव का पत्थर कहे जाते थे उन्हे भी मायावती ने पार्टी से बाहर करने में तनिक भी देर नहीं की, यही नहीं पार्टी के संस्थापक कांशीराम के साथियों को भी मायावती ने हाथी से उतरने में देर नहीं की। कुछ ऐसा सलूक मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ भी किया। हालांकि खुद मायावती बीते आठ सालों से आकाश आनंद को राजनीति के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन लंदन में पढ़ाई करने वाले आकाश आनंद दलित समाज के बीच पुराने ढर्रे की राजनीति करने की अपेक्षा स्वतंत्र और मुखर तरीके से अपनी बात कहने पर जोर देने पर अमादा थे। आकाश का यह तरीका मायावती को पसंद नहीं आ रहा था. इसे लेकर ही दोनों के बीच दूरी बढ़ी और 2 मार्च को मायावती ने जब आकाश को बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटाने की घोषणा की, तो यह 10 महीने में दूसरी बार था,

मायावती को नापसंद थे आकाश के बगावती तेवर



जब उन्होंने ऐसा फैसला लिया। मायावती ने जून 2019 में आकाश को पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया। फिर दिसंबर 2023 में उन्होने आकाश को अपना सियासी उत्तराधिकारी नामित किया। इस कदम को युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के उपाय के रूप में भी देखा गया।

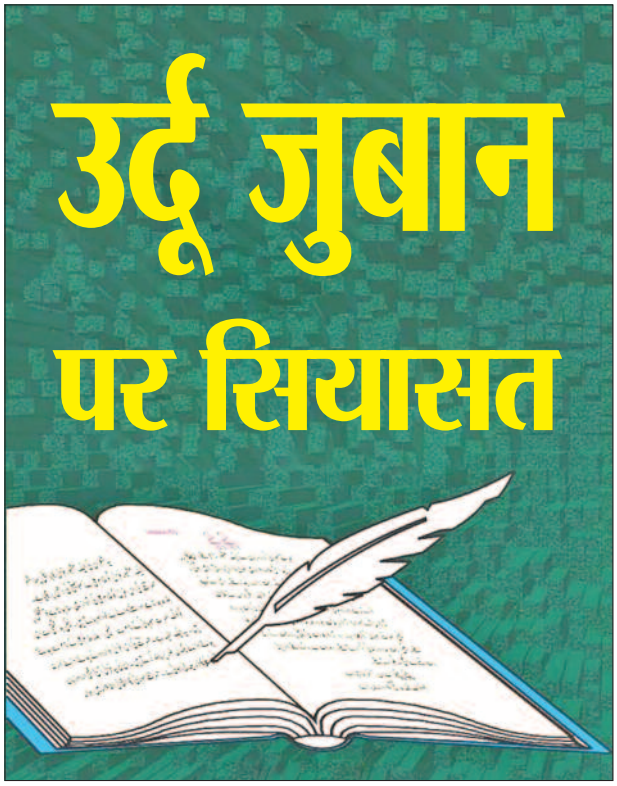
आकाश ने मायावती की देखरेख में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का जवाब देना भी शुरू किया, लेकिन अपने अंदाज में। मायावती की तरह लिखित भाषण पढ़ने के बजाए आकाश आनंद सभाओं में अपने मन ही बात रखते हुए महंगाई और बेरोजगार के मुद्दे पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को निशाने पर लेंगे गए। बीते लोकसभा चुनावों में सीतापुर की एक जनसभा में आकाश आनंद ने अपने संबोधन में अभद्र टिप्पणी कर दी। उनके तेवर को सभा में आए बसपा समर्थकों ने तो पसंद किया लेकिन प्रशासन को यह पसंद नहीं आया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में आकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई. इस मामले को लेकर मायावती खफा हुई और उन्होने आकाश को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। मायावती का यह फैसला बसपा समर्थकों को नागवार लगा और बसपा का लोकसभा चुनावों में एक भी सीट जीत नहीं सकी. बाद में अगस्त 2024 में मायावती ने आकाश आनंद को फिर प्रमुख पदों पर बहाल कर दिया था और उन्हें हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड तथा दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। लेकिन उन पर नजर रखी जाने लगी। आकाश की गतिविधियों के बारे में मायावती पार्टी के नेताओं से रिपोर्ट लेने लगी।

मायावती ने अपनी सक्रियता बढ़ाई अब हर मुद्दे पर मुखर हैं

मायावती के इस फैसले के बाद से अब यह सवाल उठा है कि आकाश के बगैर बसपा अपनी खोई सियासी जमीन कितना हासिल कर पाएगी? इसका जवाब भविष्य के गर्त में है, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि मायावती अब राजनीतिक और पारिवारिक मझधार में फंस गई हैं। उन्हे पार्टी और परिवार दोनों को एकजुट रखना है। पार्टी को एकजुट रखने और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए मायावती को जानाधार वाले नेताओं की जरूरत है। ऐसे नेता अब पार्टी में ना के बराबर हैं। खुद मायावती जनता के बीच जाती नहीं हैं। चुनावी रैली भी वह अब कम करती हैं. ऐसे में जनता के बीच दलित समाज की आवाज पार्टी का कौन नेता उठा रहा है? यह जानने के तंत्र भी मायावती के पास है नहीं। पहले मायावती के पास पार्टी में जनाधार वाले नेताओं की लंबी फौज थी, ऐसे सारे नेताओं को उन्होने पार्टी से बाहर कर दिया है. जिस आकाश आनंद के भरोसे मायावती पार्टी के आधार को बढ़ाने में जुटी थी, उसे भी उन्होने बाहर कर दिया है

वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद अपने ससुर अशोक के साथ मिलकर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए उम्मीदवारों के चयन, प्रचार कोष जुटाने और रणनीति बनाने समेत पार्टी के सारे काम करने लगे। इन दोनों ने रामजी गौतम समेत मायावती के विश्वासपात्र माने जाने वाले वरिष्ठ पार्टी नेताओं की सलाह को तबज्जो नहीं दी, क्योंकि रामजी गौतम विभिन्न जातीय अस्मिताओं के महागठजोड़ वाली पुरानी राजनीति को आगे बढ़ाने की वकालत कर रहे थे, जबकि आकाश आनंद का कहना था कि अब सिर्फ जातीय अस्मिता को उभारने वाली राजनीति से काम नहीं चलेगा। जातीय अस्मिता की जो राजनीति पार्टी लंबे समय से कर रही है वह वह अब पुरानी पड़ चुकी है। जातीय अस्मिता की चाह के स्वरूप में आज काफी परिवर्तन आ गया है। विकास की चाह, बाज़ारवादी मानसिकता और जनसमूहों के बदलते स्वरूप को देखते हुए उन्हें जातीय अस्मिता की राजनीति की नई भाषा इजाद करने की ज़रूरत है। यही भाषा आकाश आनंद अपनी सभाओं में बोलने लगे तो मायावती को पार्टी में दो फाड़ होने का डर समाया। उन्हें आकाश के तेवर भी बगावती लगे। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद मायावती के वफादारों ने उन्हें चुनाव में आकाश और अशोक की भूमिका तथा पार्टी कोष के कथित कुप्रबंधन के बारे में जानकारी दी। मायावती को यह भी बताया गया कि आकाश अपने ससुर अशोक के साथ मिलकर राज्यों में संगठन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या था, मायावती ने पहले तो पहले तो अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद के लिए पार्टी के दरवाजे खोले। फिर उन्होंने 12 फरवरी को आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित करने के ऐलान किया। इसी दरमियान मायावती ने अपने भाई अपने भाई आनंद कुमार पर भरोसा जताया और पार्टी पर पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने आनंद कुमार और रामजी गौतम को राष्ट्रीय समन्वयक बनाया और यह ऐलान भी किया कि जब तक वे जीवित हैं, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा।

और अब मायावती को खुद ही हर मुद्दे पर आगे आकर बोलना पड़ रहा है। बीते दिनों होली के ठीक पहले आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का बहुत व्यापक असर भले ही न दिखा हो लेकिन राजधानी से लेकर अन्य जिलों तक जिस तरह से प्रशासन ने उनके प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए उसे रोकने की तैयारी की, उसका संदेश जरूर व्यापक गया। जिसका संज्ञान लेते हुए मायावती ने पार्टी समर्थको को यह संदेश दिया कि छोटे दलों का समर्थन कर बड़े दल बसपा को चुनौती दे रहे हैं, इनके भ्रम में नहीं फसना है। हमारे लिए भाई-बहन एवं अन्य रिश्ते-नाते मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, इसके सिवाय कुछ नहीं। पार्टी के हित में बहुजन समाज के जो लोग भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से काम करते हैं, उन्हें पार्टी में आगे बढ़ने का मौका जरूर दिया जाएगा। मायावती की इस सफाई को संभावनाओं के अभाव में दूसरे दलों की ओर देख रहे लोगों को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि मायावती लगातार जनाधार खोती जा रही बसपा को फिर से कैसे खड़ा करती हैं।



सगी बहनों का जो रिश्ता है, उर्दू और हिन्दी का।
कहीं दुनिया की दो जिन्दा जबानों में नहीं मिलता ।।

मरहूम शायर मुनव्वर राणा के इस शेर को अगर हम हकीकत मान कर यूपी की सियासत को समझने की कोशिश करें तो दो सगी बहनों को जुदा करने की कोशिश की जा रही है। उर्दू को तवज्जो पहले ही कम मिल रही थी, अब उर्दू अकादमी उपेक्षा का शिकार हैं। सितम्बर 2023 से उर्दू अकादमी के चेयरमैन का पद खाली है, जिसकी वजह से दफ्तर पर सन्नाटा पसरा रहता है। वर्ष 1972 में उर्दू एकेडमी वजूद में आई थी, जिस पर आज संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले तीन साल से अकादमी अपने अवार्ड नहीं बाँट सकी है। उर्दू अकादमी का खस्ताहालत के बीच अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के लाईव अनुवाद से उर्दू को बाहर रखा गया है, विधान सभा की कार्यवाही हिन्दी में होती है, जिसका अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं अवधी, भोजपुरी, बुन्देली और ब्रज भाषा में लाइव अनुवाद की सुविधा होगी। विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना के इस फैसले का विपक्षी दल विरोध कर रहें हैं। अब इस मुद्दे पर लखनऊ से लेकर दिल्ली और हैदराबाद तक में सियासत अपने उरुज पर है, **'द न्यूज कार्नर'** की खास स्टोरी में पढ़िए उर्दू को लेकर क्यों हो रही सियासत।

शारिब जाफरी

लखनऊ। उर्दू अकादमी के विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। सफेद रंग की बदरंग इमारत प्रदेश में उर्दू की हालत को बयान करने के लिए काफी है। वर्ष 1972 में कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री थे, उर्दू को बढ़ावा देने को लेकर सरकार ने एतिहासिक फैसला लिया। प्रदेश में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। जिस के बाद से उर्दू अकादमी ने उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। बच्चों के लिए साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन, प्राचीन उर्दू कृतियों का संपादन और प्रकाशन, छात्रों को स्कॉलरशिप योजनाओं ने उर्दू अकादमी को इस भाषा के कद्रदानों के बीच लोकप्रिय बना दिया।

उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद 28 जनवरी 2018 आसिफा जमानी को उर्दू अकादमी का चेयरमैन बनाया गया, उनका कार्यकाल जनवरी 2020 में खत्म हो गया। उस के बाद लम्बे वक्त तक यह पद खाली रहा। 25 सितम्बर 2021 को समाजसेवी चौधरी कैफुल वरा अंसारी उर्दू अकादमी के चेयरमैन बनाए गए, वो चौधरी हाउस गोरखपुर के रहने वाले थे, उन को मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाना था, कैफुल वरा के चेयरमैन बनाए जाने के बाद उर्दू अकादमी के दफ्तर की रौनक बढ़ गई। उर्दू, बोलने, सीखने वालों को उम्मीद जगी की शायद जो काम रुके हुए थे वो शुरू हो जाएँ, लेकिन आप को जान कर हैरत होगी कि पिछले तीन बरसों से उर्दू अकादमी अपना सालाना अवार्ड नहीं बाँट पाई है। उर्दू अकादमी हर साल 150 शायरों और साहित्यकारों को 50 लाख रुपये के पुरुस्कारों का वितरण करती है, इस में मौलाना आजाद पुरुस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार को 5 लाख रुपये की धनराशि दी जाती हैं, जबकि पुरुस्कार की सब से कम राशि 10 हजार रुपये है। अकादमी के पुरुस्कारों के लिए शायरों और साहित्यकारों के नाम कार्यकारिणी तय करती है, चेयरमैन की मंजूरी के बाद पुरुस्कार वितरित किए जाते हैं, लेकिन सितम्बर 2023 में उर्दू अकादमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा अंसारी के साथ साथ कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म हो जाने की वजह पुरुस्कार नहीं बांटे जा रहे हैं।

कैफुल वरा अंसारी का कार्यकाल पूरा होने के बाद से उर्दू अकादमी के दफ्तर के इर्द गिर्द सन्नाटा पसरा रहता है। अकादमी के 30 से ज्यादा कर्मचारियों के पद खाली हैं, जो बचे हैं, वो गुटबाजी का शिकार हैं। बीते तीन साल में अकादमी के तीन सचिव बदले जा चुके हैं। लेकिन हालात जैसे के तैसे बने हूए हैं,



दरअसल उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का दायरा बढ़ा है, ऐसे में उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1976 में फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की स्थापना की गई। विभूतिखण्ड स्थित उर्दू अकादमी की बिल्डिंग के चौथे माले पर टंगा बैनर फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के दफ्तर का पता है। कमेटी के चेयरमैन की कुर्सी लम्बे वक्त से खाली है, जिसकी वजह से दफ्तर कामकाज ठप हो गया है। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी और उर्दू अकादमी के सचिव की जिम्मेदारी शौकत अली संभाल रहे हैं। वो कहते हैं, कि उर्दू अकादमी और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की योजनाओं के संचालन पर चेयरमैन के नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हकीकत ये है, की बीते तीन सालों मे उर्दू अकादमी शायरों और साहित्यकारों को मिलने वाले अवार्ड नहीं बाँट सकी है।

विधानसभा में लाइव अनुवाद से उर्दू बाहर

भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उर्दू से भेदभाव के आरोप के चलते विधान सभा में बजट सत्र के दौरान 18 फरवरी को सत्र के पहले दिन जम कर हंगामा हुआ। सदन में विवाद की शुरुआत तब हुई, जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही के अंग्रेजी अवधी, भोजपुरी, बुन्देली और ब्रज भाषा में लाइव अनुवाद की व्यवस्था करने की घोषणा की। इस व्यवस्था के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के संबोधन का हिन्दी में लाइव अनुवाद करने की सुविधा शुरू की, अगर सदस्य सदन में भोजपुरी, अवधी, बुन्देली में बोलना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर सदस्य क्षेत्रीय बोलियों भोजपुरी, अवधी, बुन्देली और ब्रज भाषा में से किसी दूसरे सदस्य का संबोधन सुनना चाहते हैं, तो उन्हें अब अपनी सीटों पर संबंधित चैनल का चयन करने की सुविधा है, ताकि वे अपने ईयर प्लग में लाइव अनुवाद सुन सकें। उत्तर प्रदेश विधान सभा की आधिकारिक भाषा हिन्दी है, इसलिए अंग्रेजी से किसी भी शब्द का उपयोग करने वाले सदस्यों को उसका हिन्दी अनुवाद प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

सदन में नई व्यवस्था लागू होने के बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने अनुवाद के लिए निर्धारित भाषाओं की लिस्ट में उर्दू को छोड़ अंग्रेजी शामिल करने पर एतराज जताया। उन्होंने कहा, हम सदन में सदस्यों पर अंग्रेजी थोपे जाने का विरोध करते हैं। यह सुविधा उर्दू में क्यों नहीं हो सकती है, उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने अंग्रेजी के खिलाफ आन्दोलन चलाया था और जेल भी गए थे। ऐसे में विधान सभा में लाईव अनुवाद के लिए अंग्रेजी की सुविधा प्रदान करने के फैसले का विरोध किया जाएगा। माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि, हम विधानसभा को उच्च वर्ग के लोगों का सदन नहीं बनने

देशभर में उर्दू अकादमी के हाल एक जैसे



देश भर में उत्तर प्रदेश की उर्दू अकादमी से मिलते-जुलते हालात अन्य अकादमियों के भी है। दरअसल, केन्द्र सरकार ने अक्तूबर 2006 में उर्दू भाषा के विकास के लिए देश को तीन जोन में बांटकर तीन विश्वविद्यालयों में उर्दू अकादमी बनाने पर सहमति दी थी, जिस के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली की अकादमी के पास दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के उर्दू शिक्षकों को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उर्दू अकादमी पर बिहार, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा जबकि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पास दक्षिण भारतीय राज्यों का जिम्मा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद को 4-4 करोड़ रुपए भी दिए गए। उर्दू अकादमियों में मदरसों और उन शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता था, जहां पर उर्दू पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।



अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) की उर्दू अकादमी के पूर्व निदेशक डाक्टर राहत अबरार कहते हैं, कि मैं 2016 से 2020 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उर्दू अकादमी का निदेशक रहा। इस दौरान उर्दू अकादमी को बजट नहीं मिला। वो कहते हैं, पिछले 8 साल से अकादमी का बजट बंद है, जिस की वजह अकादमी से संचालित होने वाले सभी कार्यक्रम भी बंद हैं। कुछ ऐसे ही हालात जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में स्थापित उर्दू अकादमियों के भी हैं।

एएमयू में उर्दू विभाग के एडवांस स्टडी सेंटर के बंद होने से भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग में हो रहे शोध कार्यों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 2013 में एडवांस स्टडी सेंटर शुरू करने के लिए अनुदान दिया था। अनुदान पांच साल के लिए था, जिसमें उर्दू के लिए 99 लाख रुपए और अरबी के लिए 90 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। वर्ष 2018 में फिर अनुदान मिला। जिसकी मियाद 2023 तक थी। लेकिन अप्रैल 2023 में यूनिवर्सिटी को पांच साल के लिए जो अनुदान मिलना था, वो नही मिला। जिस की वजह से एडवांस स्टडी सेंटर के जरिए उर्दू छात्रों के लिए होने वाली कार्यशाला, सेमिनार और विख्यात उर्दू लेखकों के व्याख्यान का आयोजन बन्द हो गया है, यूनिवर्सिटी के छात्रों के दबाव के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उर्दू अकादमी और एडवांस स्टडी सेंटर के लिए बजट की व्यवस्था करने के लिए यूजीसी के दफ्तर पर दौड़ भाग शुरू की है।







उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का लाईव अनुवाद अंग्रेजी, अवधी, भोजपुरी, बुन्देली और ब्रज भाषा में होगा, लेकिन उर्दू में नहीं। सरकार के इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने सवाल खड़े करते हुए। अंग्रेजी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है।



सहारनपुर से काँग्रेस साँसद इमरान मसूद कहते हैं, कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है, मुख्यमन्त्री को फिराख गोरखपुरी को पढ़ना चाहिए।

प्रदेश में अवधी, ब्रज और बुंदेली भाषा से ज्यादा बोल चाल की भाषा में उर्दू इस्तेमाल होती है, ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही में उर्दू को शामिल न करना इस प्रक्रिया पर संदेह पैदा करता है, उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार उर्दू के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है।

- माता प्रसाद पाण्डेय, नेता प्रतिपक्ष

देंगे। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, सरकार विधान सभा अध्यक्ष के बचाव में खड़ी नजर आई। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष की पहल का बचाव किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशान साधते हुए कहा, सपा अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाएगी और जब आम जनता के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है, तो ये लोग उर्दू थोपने की वकालत करने लगते हैं। मुख्यमन्त्री ने आरोप लगाया कि सपा मौलवी बनाना चाहती है, कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सदन में मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान के बाद वो विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, काँग्रेस साँसद इमरान मसूद और एआईएआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर निशाना साधा है, अखिलेश यादव ने कहा, यह पहली सरकार है जो उर्दू का विरोध उर्दू में कर रही है, मुख्यमन्त्री ने कई बार उर्दू के शब्द बोले। पायदान, गुनहगार, बख्शा नहीं जाएगा, बदनाम, पैदा, मौत, सरकार क्या ये उर्दू शब्द नहीं हैं। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार पर उर्दू भाषा के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाकर सदन के बाहर भी इस मुद्दे को ले जाने की तैयारी कर रही है। माता प्रसाद पाण्डेय कहते हैं, बजट सत्र के बाद हम विधानसभा में अंग्रेजी को बाहर करने और उर्दू को अनुवाद भाषा के तौर पर शामिल करने के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के खिलाफ लड़ाई इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमारे नेताओं ने अंग्रेजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगर यूपी ऐसा नहीं करेगा तो कौन करेगा। उर्दू का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी।

राजनीति के जानकार बताते हैं, कि उर्दू को सियासत का मुद्दा बना कर राजनीतिक दल अपने एजेंडे को साधने की कोशिश करेंगें। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह कहते हैं, कि 2027 के विधान सभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण वाले मुद्दों को हवा देने की कोशिश करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा उर्दू को मुसलमानों की भाषा समझ कर अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। राज कुमार सिंह कहते हैं, कि उर्दू की संवैधानिक वैधता है, क्योंकि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उर्दू समेत 14 भाषाओं को परिभाषित किया गया है। वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय रूप से यह सिद्ध है, कि उर्दू एक स्वदेशी भाषा है।

सितम्बर 1989 में तत्कालीन मुख्यमन्त्री नारायण दत्त तिवारी सरकार ने उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देते हुए उत्तर प्रदेश आधिकारिक भाषा संशोधन अधिनियम, 1989 को पास कराया था, जिस के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के 16 सदस्यों ने वोट किए थे। संशोधन विधेयक में कहा गया था, कि उर्दू भाषा और उर्दू बोलने वाले लोगों के हित में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। विधान सभा में उत्तर प्रदेश आधिकारिक भाषा संशोधन अधिनियम, 1989 के पास होने के बाद बदायूं में उर्दू समर्थक और विरोधी गुटों के बीच हिंसा हुई, जिसमें एक दर्जन लोगों की जान चली गई थी।

उत्तर प्रदेश में उर्दू को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के पैंतीस साल बाद, राज्य विधानसभा में मचे हंगामे ने भाषा की स्थिति पर विवादास्पद मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया है, उर्दू भाषा हो या फिर कोई दूसरा ध्रुवीकरण का मुद्दा जब जब गरमाया भाजपा को फायदा हुआ है। उर्दू को सितम्बर 1989 में दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली, तो भाजपा की भी राजनैतिक उड़ान भी शुरू हो गई, नवम्बर 1989 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें 16 से बढ़कर 57 हो गईं। इस बीच उर्दू को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। यूपी हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उर्दू भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने वाले कानून को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, इस मामले पर पांच जजों की बेंच ने सुनवाई की, अदालत ने 2014 में याचिका खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव सरकार ने राज्य में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने का आदेश जारी कर दिया। ●

एक नजर

1 बीयूएमएस में उर्दू की अनिवार्यता खत्म

उत्तर प्रदेश में यूनानी मेडिकल कॉलेजों में बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के वक्त उर्दू की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र ने अगर विषय के रूप में उर्दू, अरबी, फारसी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो उसे पढ़ाई के पहले सेमेस्टर में अरबी, मंतिक व फलसफा (लॉजिक एंड फिलॉसफी) के साथ उर्दू भाषा का भी अध्ययन करना होगा।

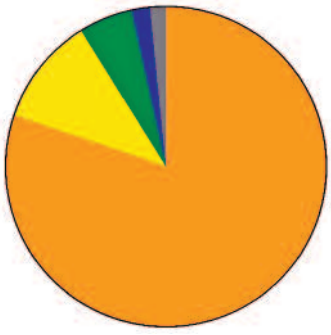
2 उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती पर लगाई गई रोक

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 से पहले दिसम्बर 2016 में उर्दू के 4,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरु की थी। 19 मार्च 2017 को सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने 22-23 मार्च 2017 को प्रदेश भर में उर्दू शिक्षक भर्ती के लिए काउंसिलिंग की गई। लेकिन 23 मार्च, 2017 को ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने उर्दू के सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। करीब डेढ़ साल बाद अक्तूबर 2018 को पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी गई।

3 रामपुर में स्वार मार्ग पर बने उर्दू गेट पर चला बुलडोजर

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व नगर विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खान ने अपने जिले रामपुर में स्वार मार्ग पर 2016 में आलीशान उर्दू गेट का निर्माण कराया था। उर्दू गेट के निर्माण पर 40 लाख रुपये का खर्च आया था, लेकिन वर्ष 2019 में रामपुर प्रशासन ने उर्दू गेट को अवैध निर्माण का हवाला देते हुए बुलडोजर से गिरा दिया।

यूपी में भाषाएं



- हिंदी - 80.16 प्रतिशत
- भोजपुरी - 10.93 प्रतिशत
- उर्दू - 5.42 प्रतिशत
- अवधी - 1.9 प्रतिशत
- अन्य - 1.59 प्रतिशत

(**स्रोत :** जनगणना-2011)

यहां होता है उर्दू का इस्तेमाल

- सरकार की मंशा थी, कि उर्दू में याचिकाओं और आवेदनों को स्वीकार किया जाए और उस का जवाब उर्दू में दिया जाए
- पंजीकरण कार्यालयों में उर्दू में लिखे दस्तावेज स्वीकार करना
- महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में प्रकाशन
- सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेश और परिपत्र उर्दू में जारी करना शामिल है।

उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाए जाने के बाद उर्दू राजनीति का शिकार हो गई है, सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रोकना और पाठ्य पुस्तकों में बदलाव इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। रही सही कसर विधान सभा की कार्यवाही के लाईव अनुवाद के लिए अंग्रेजी को शामिल कर उर्दू से दूरी बना कर राजनीति को गर्मा दिया है।

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कक्षा एक एवं दो के उर्दू माध्यम और मदरसों की पुस्तकों में बड़ा बदलाव किया गया है। उर्दू सिखाने के लिए परिषदीय विद्यालयों में उर्दू माध्यम के कक्षा एक और मदरसों में पढ़ाई जा रही उर्दू जबान किताब बंद कर दी गई है। इस की जगह पर शहनाई पुस्तक शामिल की गई है। जो उर्दू विषय की किताब है।

उर्दू को लेकर हो राजनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि महाकुम्भ से शाही शब्द को हटा दिया गया। अखाड़ा परिषद के संतों के अनुरोध पर प्रयागराज महाकुंभ में योगी सरकार ने उर्दू और फारसी शब्दों के प्रयोग में बदलाव किया। शाही की जगह अमृत शब्द का इस्तेमाल किया गया। महाकुम्भ में प्रमुख स्नान तिथियों में अखाड़ों के साधु-संत संगम में स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता था। इस बार महाकुंभ में उर्दू शब्द शाही की जगह अमृत शब्द का इस्तेमाल किया गया। शाही स्नान को वर्ष 2025 के महाकुम्भ में अमृत स्नान कहा गया।



उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी कहते हैं, सरकार अन्य भाषाओं की तरह उर्दू की बेहतरी के लिए भी काम कर रही है।



एआईएमआईएम अध्यक्ष व हैदराबाद से साँसद असदुदीन ओवैसी कहते हैं, मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ को तो उर्दू नहीं आती है, फिर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन गए।



अज़्म शाकिरी



ख़ुर्शीद मुजफ्फरनगरी



अंजुम रहबर



डॉ. बलवंत सिंह



जमुना प्रसाद उपाध्याय



नदीम फर्रुख



मंजर भोपाली



फखरी मेरठी



अमीर इमाम



बिलाल सहारनपुरी



शाहिद कमाल



हिमांशी बाबरा



मोहम्मद अली साहिल



इब्राहिम अली



सागर बनारसी


जहाज देवबंदी

















'द न्यूज कॉर्नर' द्वारा आयोजित मुशायरा व सम्मान समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कंवेंशन सेंटर में 22 फरवरी 2025 को सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस शमीम अहमद व अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने समारोह की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर रिटायर्ड आईएएस महेश गुप्ता, पूर्व अपर शासकीय महाधिवक्ता इमरान उल्लाह खां, अपर जिला जज सोनभद्र आबिद शमीम, महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. मधु गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शारिक अब्बासी, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार, आनंद राय और मोहम्मद इशहाक को जस्टिस शमीम अहमद, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मौलाना कल्बे रुशैद, मौलाना शाह फजलुर मन्नान और द न्यूज कॉर्नर के सम्पादक सैय्यद आसिफ़ रज़ा जाफ़री के हाथों सम्मानित किया गया। इस मौके पर देश व दुनिया के मशहूर शायरों ने अपने कलाम पढ़े।







'द न्यूज़ कॉर्नर' द्वारा आयोजित मुशायरे व सम्मान समारोह में जस्टिस शमीम अहमद (मद्रास हाईकोर्ट), पूर्व मंत्री व विधायक शिवपाल सिंह यादव, पूर्व वरिष्ठ आईएएस महेश गुप्ता, मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी, विश्व प्रसिद्ध शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे रुशैद, मुस्लिम स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपने विचार रखे। इस मौके पर प्रसिद्ध दास्तानगो कफील जाफरी और सहयोगी युसरा ने बेगम अख्तर के जीवन पर आधारित दास्तानगोई 'दास्तान-ए-अख्तरी' प्रस्तुत की।














दन्यूज़ कॉर्नर


FOUNDATION DAY




THE NEWS C
Present
2ND
THE NEWS CO













औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंकने की हुंकार

इतिहास के पन्नों से सियासत के मैदान तक

उस्मान सिद्दीकी



महाराष्ट्र। सपा विधायक अबू आसिम आजमी के मुगल बादशाह औरंगजेब पर दिए बयान के बाद से देश में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 318 वर्षों के बाद अब औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंकने के लिए हुंकार भरी जा रही है। विवाद सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी इस का असर देखने को मिला है। औरंगजेब को 17वीं सदी में अपने शासन और धार्मिक नीतियों के लिए जाना जाता है, जो एक बार फिर विवादों के केन्द्र में है। हाल के दिनों में नेताओं के बयान, फिल्म और उनकी कब्र ने देशभर में सियासी और सामाजिक तनाव को हवा दी है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश विधान सभा से सड़कों तक औरंगजेब का नाम गूंज रहा है, कहीं उनकी क्रूरता की चर्चा है, तो कहीं उनके प्रशासन की तारीफ। औरंगजेब पर विवाद अब केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहा है, जिस की वजह से पुणे महाराष्ट्र में हिंसक झड़प हुई है, आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

विवाद की जड़ में अबु आसिम आजमी का बयान और फिल्म छावा

मुगल शासक औरंगजेब पर ताजा विवाद की जड़ हाल में रिलीज हुई फिल्म 'छावा' से जुड़ी है। फिल्म मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की जिन्दगी और शासन के इर्द गिर्द केन्द्रित है। इस फिल्म में अभिनेता विक्की कौशल ने संभाजी और अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया है। फिल्म में संभाजी के साहस और औरंगजेब द्वारा उनकी क्रूर हत्या को भावनात्मक ढंग से दिखाने की कोशिश की गई है। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को यातनाएँ देकर मरवा दिया था, जिसे मराठा इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। इस फिल्म ने लोगों में संभाजी के प्रति सम्मान और औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा जगा दिया।

इसी बीच, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसिम आजमी ने 3 मार्च 2025 को एक बयान दिया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। अबू आसिम आजमी ने कहा, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, बल्कि उसके शासनकाल में भारत सोने की चिड़िया बना। उसने कई मन्दिर बनवाए और उसकी लड़ाई धर्म की नहीं, सत्ता की थी। अबू आसिम आजमी के इस बयान के बाद देश की सियासत गरमा गई। महाराष्ट्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने इसे मराठा भावनाओं का अपमान बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, अबू आसिम आजमी का 100 फीसदी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इसके बाद से अटकलें लग रही है, कि देर सबेर अबू आसिम आजमी को जेल जाना पड़ सकता है, हालांकि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से पहले तमाम सबूतों को जुटाने में लगी है। संभावना व्यक्त की जा रही है, कि जब पुलिस अबू आसिम आजमी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर फैसला लिया जाए। औरंगजेब को लेकर बयान देने वाले अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलम्बित किया गया था, तब उन्होंने कहा था, कि मेरा निलम्बन सरकार की मनमानी है, मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र में दो कानून चल रहे है, अगर महाराष्ट्र में लोकतंत्र खत्म हो चुका है तो सरकार जनता के साथ और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ कुछ भी कर सकती है। अबू आसिम आजमी के बयान से उपमुख्यमन्त्री एकनाथ शिंदे भी खफा हैं, उन्होंने कहा, कि औरंगजेब की तारीफ करना महाराष्ट्र की विरासत का अपमान है। अबू आसिम आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।

सियासी हंगामा और कानूनी कार्रवाई



अबू आसिम आजमी के बयान के बाद 4 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और अबू आसिम आजमी के खिलाफ नारेबाजी की। 5 मार्च को अबू आसिम आजमी को मौजूदा सत्र के लिए विधानसभा से निलम्बित कर दिया गया। इसके साथ ही ठाणे में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएँ भड़काने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की गई है। विवाद बढ़ता देख अबू आसिम आजमी ने सफाई दी, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने शिवाजी या संभाजी महाराज के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतिहासकारों के हवाले से औरंगजेब के बारे में बोला। लेकिन उनकी सफाई का कोई असर नहीं हुआ। 6 मार्च को अबू आसिम आजमी ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात कही, जिससे जंग और गहरा गई।

यूपी भेज दीजिए, इलाज हम कर देंगे : योगी आदित्यनाथ

महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर से सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने बयान महाराष्ट्र में दिया लेकिन उसकी गूंज यूपी विधान सभा में भी सुनाई दी। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भारत की विरासत संस्कृति को कोसना मानों सपा के जीवन का उद्देश्य हो गया है,

दुर्भाग्य है कि इन्होंने औरंगजेब को अपना आदर्श माना है, जबकि औरंगजेब का पिता अपनी आत्मकथा में लिखता है, कि ऐसा बेटे किसी को पैदा न हो उसने अपने बाप को आगरा में कैद करके रखा, एक-एक बंदू पानी के लिए तरसाया। सीएम ने सपा विधायक अबू आसिम आजमी पर निशान साधते हुए, कहा कि उनके बयान पर सपा को जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर आक्रमण करने वाले क्रूर शासक को सपा आदर्श मानती है, लेकिन कोई भी सभ्य मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता। मुख्यमन्त्री ने सपा से अबू आसिम आजमी को पार्टी से निकालने की मांग की और कहा कि उसे एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी का उपचार हम कर देंगें। सीएम के इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने मुख्यमन्त्री पर निशाना साधा, उन्होंने कहा, वे घोर सांप्रदायिक हो गए हैं। हमारे संविधान में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि, क्या मुख्यमन्त्री की भाषा ठीक है। माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा की मुख्यमन्त्री का बयान बहुत ही खतरनाक है, अबू आसिम आजमी ने ऐसी कोई बात नहीं की, जिस से उनको प्रताड़ित किया जा सके।

इतिहास में सच क्या

औरंगजेब 1658 से 1707 तक मुगल बादशाह रहा, जो अपने 49 साल के शासनकाल में विवादों से घिरा रहा। इतिहासकार उसे दो नजरियों से देखते हैं। एक तरफ, वह अपने साम्राज्य के विस्तार और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उसके समय में भारत की जीडीपी दुनिया की 24 प्रतिशत थी और सीमाएँ अफगानिस्तान से बर्मा तक फैली थीं। दूसरी तरफ, उसकी धार्मिक नीतियाँ जैसे जजिया कर लागू करना और हिंदुओं पर कथित अत्याचार उसे कट्टर और दमनकारी शासक के रूप में पेश करती है।

राजनीतिक दलों की रणनीति

औरंगजेब विवाद में हर दल अपनी रोटियां सेंक रहा है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट इसे हिंदुत्व और मराठा गौरव से जोड़कर विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। विवाद सपा विधायक अबू आसिम आजमी के बयान देने के बाद शुरू हुआ है, ऐसे में समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। 'छावा' फिल्म के हिट होने, अबू आसिम आजमी के बयान के बाद नागपुर महाराष्ट्र की घटना और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा दिखाता है, कि औरंगजेब का नाम आज भी भावनाएँ भड़काता है। ●

नागपुर में सड़कों पर तनाव



औरंगजेब पर फिल्म और अबू आसिम आजमी के बयान से शुरू हुआ विवाद 17 मार्च 2025 को हिंसक रूप लेता दिखाई दिया। सुबह नागपुर महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी चौक पर औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और उनकी प्रतीकात्मक प्रतिमा जलाने की कोशिश की, जिस के बाद शाम होते होते चिटनीस पार्क इलाके में मुस्लिम युवकों ने इसका विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों समूहों में तनाव बढ़ा और पथराव शुरू हो गया। कुछ वाहनों में आगजनी भी हुई है। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक माहौल तनावपूर्ण, लेकिन नियंत्रण में है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडवीस ने पुलिस को सख्ती करने के लिए कहा है। सीएम ने कहा की उपद्रव करने वाले शरारती तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

औरंगजेब से जुड़ी संरक्षित इमारत

- औरंगजेब का मकबरा, खुलदाबाद, संभाजी नगर महाराष्ट्र
- औरंगजेब का किला, मचनूर, सोलापुर महाराष्ट्र
- बाग बादशाही, फतेहपुर उत्तर प्रदेश धरहरा मस्जिद, वाराणसी, यूपी
- नवबाग (औरंगजेब की पत्नी की कब्र) विजयपुरा कर्नाटक

औरंगजेब की कब्र कहाँ है

- सं. 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था
- औरंगजेब की कब्र खुलदाबाद संभाजी नगर में है शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया
- औरंगजेब ने अपनी वसीयत में दफनाने के लिए कहा था
- 1951 में औरंगजेब की कब्र संरक्षित इमारत घोषित हुई, जिसकी देखरेख एएसआई के पास है
- 1958 में राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित की गई
- एएमएएसआर एक्ट के तहत कब्र को नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है, इसमें कब्र को तोड़ा, हटाया या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।
- जब तक कब्र एएसआई के संरक्षण में है महाराष्ट्र सरकार इसे हटा नहीं सकती



मुगल शासनकाल से अब तक जीडीपी में हिस्सेदारी

- 1700 में ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी करीब 24 फीसदी
- 1947 ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदारी घट कर सिर्फ 3 फीसदी
- अंग्रेजों ने देश की 45 ट्रिलियन डालर यानि 3,906 लाख करोड़ की सम्पत्ति लूटी
- मौजूदा वक्त में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 28 ट्रिलियन डालर की है, रुपये में ये 2,430 लाख करोड़ है
- भारत ने 2029 तक 5 ट्रिलियन डालर का लक्ष्य रखा है, जो अंग्रेजों द्वारा लूटी गई सम्पत्ति से 9 गुना कम है

शेयर मार्केट में तबाही

निवेशकों के 95 लाख करोड़ रुपये डूबे

टीएनसी ब्यूरो



मुम्बई। भारतीय शेयर के बाजार में आई भारी गिरावट ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले पांच महीनों से लगातार गिरावट का शिकार है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से क्रमशः 13.23 प्रतिशत और 14.19 प्रतिशत नीचे आ चुके हैं। यह ऐसी मंदी है, जो पिछले 30 सालों में कभी नहीं देखी गई। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बाजार लगातार पांच महीनों तक गिरा हो। निवेशकों के करीब 95 लाख करोड़ रुपये डूब चुके हैं, और छोटे निवेशकों में हाहाकार मचा हुआ है। इस गिरावट ने करोड़ों निवेशकों को प्रभावित किया है, और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह भूचाल क्यों आया? कितना नुकसान हुआ? कितने लोगों को चोट पहुंची? और इससे पहले सबसे बड़ी गिरावट कब देखी गई थी? आइए, इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं।

क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट?

पिछले पांच महीनों में शेयर बाजार में भारी गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जिन्हें विशेषज्ञों ने चिन्हित किया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (स्रढ्ढढ्ढ) ने पिछले पांच महीनों में भारतीय बाजार से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं। इसका मुख्य कारण सरकार का कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने का फैसला बताया जा रहा है। हेलियोस कैपिटल के संस्थापक समीर अरोड़ा ने कहा, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर सरकार ने विदेशी निवेशकों को नाराज कर दिया। सॉवरेन फंड्स और पेंशन फंड्स अब भारत में निवेश को जोखिम भरा मान रहे हैं। पिछले दो महीनों में ही FII ने 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बिकवाली की।

अमेरिकी व्यापार तनाव व ट्रंप की नीतियाँ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियाँ भी इस गिरावट का बड़ा कारण बताया जा रहा है। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामान पर 25त्न टैरिफ लागू करने का ऐलान किया, जो 4 मार्च 2025 से प्रभावी हो गया। इसके अलावा, चीन और यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की। इन नीतियों ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता पैदा की, जिसका असर भारतीय बाजार पर पड़ा।

उम्मीद से कम रहे कारपोरेट के नतीजे

तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024) के कॉरपोरेट नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे। रिलायंस, एशियन पेंट्स, और इंडसइंड बैंक जैसे बड़े नामों ने निवेशकों को निराश किया। मास्टर ट्रस्ट ग्रुप के निदेशक पुनीत सिंघानिया ने कहा, कंपनियों के कमजोर नतीजों ने निवेशकों का भरोसा तोड़ा। साथ ही, भारत की आर्थिक ग्रोथ भी धीमी हुई, जो दिसंबर तिमाही में 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

कितने साल का रिकॉर्ड टूटा?

1996 में जुलाई से नवंबर तक बाजार पांच महीने गिरा था। इसके बाद 2024-25 में यह पहली बार हुआ कि अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगातार पांच महीनों की गिरावट दर्ज की गई। फरवरी 2025 में निफ्टी के 4 प्रतिशत गिरने के साथ यह 28 साल में पहली बार हुआ कि बाजार ने लगातार पांच महीनों की मंदी देखी। इसके अलावा जनवरी 2008 में सेंसेक्स 21,000 से गिरकर अक्टूबर 2008 में 8,000 के स्तर पर आ गया था, जो 62 प्रतिशत की गिरावट थी। निवेशकों को करीब 50 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। कोरोना काल में यानी मार्च 2020 में सेंसेक्स 39,000 से गिरकर 25,000 पर आ गया, जो 36 प्रतिशत की गिरावट थी। निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 1992 का हर्षद मेहता घोटाला किसे नहीं याद होगा। इस घोटाले के सामने आने के बाद 1992 में सेंसेक्स 4,500 से गिरकर 2,000 के स्तर पर आ गया, जो 55 प्रतिशत की गिरावट थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि संयम रखने का है। इसके लिए वॉरेन बफेट का सिद्धांत अपनाया जा सकता है। यह सिद्धांत है.. जब दूसरे डरे हुए हों, तो लालची बनो। डेटा दिखाता है कि 10 % की गिरावट के बाद अगले एक साल में बाजार ने हमेशा बंपर रिटर्न दिया है।

वैश्विक अनिश्चितता

भारतीय शेयरों का मूल्यांकन पहले ही ऊँचे स्तर पर था, जिससे निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू की। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के प्रशांत तापसे कहते हैं कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने, डॉलर में मजबूती, और रुपये में कमजोरी ने विदेशी निवेशकों को भारत से दूर किया है।

चीन की ओर निवेश का रुख

चीन में आर्थिक पैकेज की घोषणाओं ने निवेशकों को वहाँ आकर्षित किया। अक्टूबर 2024 से अब तक भारत का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन डॉलर घटा, जबकि चीन का 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा। क्लम्प्रद्ध सिक्योरिटीज के अनुसार, चीन में निवेश की मांग बढ़ी, जबकि भारतीय शेयरों का आकर्षण घटा है।

कितना नुकसान हुआ?

पिछले पांच महीनों में बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 25 लाख करोड़ की गिरावट आई है। 26 सितंबर 2024 को मार्केट वैल्यूएशन 171 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर था, जो अब घटकर 146 लाख करोड़ रुपये रह गया है। इसके अलावा, निवेशकों के कुल नुकसान को देखें तो पिछले पांच महीने में 95 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। केवल फरवरी माह में ही निफ्टी में 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। बीएसई मिडकैप 20 प्रतिशत और स्मॉलकैप 22.78 प्रतिशत गिर चुका है। भारत में करीब 10 करोड़ रिटेल निवेशक हैं, जिनमें से 60-70 प्रतिशत ने इस गिरावट में नुकसान उठाया। जनवरी 2025 में 5.14 लाख SIP खाते कम हुए, जो निवेशकों के डर को दर्शाता है। छोटे निवेशकों, जिनके पास मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर थे, को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ट्रेंट, एशियन पेंट्स, और टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में 31-33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

नौजवानों की किस्मत खुली

यूपी पुलिस में 60,244 नए रंगरूट भर्ती

पवन कुमार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 13 मार्च 2025 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया, जिसके साथ ही 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची सामने आई। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 48,17,441 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, और कड़ी मेहनत व पारदर्शी चयन प्रक्रिया के बाद सफल अभ्यर्थियों को अब अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला है। बोर्ड अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने इसे होली का तोहफा बताते हुए सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी है। लेकिन सवाल यह है कि अब चयनित अभ्यर्थियों को आगे क्या करना होगा?

भर्ती प्रक्रिया का सफर

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की शुरुआत 23 दिसंबर 2023 को विज्ञापन जारी होने के साथ हुई थी। आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक चली। इसके बाद लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को 67 जिलों में 10 पालियों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में आधार सत्यापन और फिंगरप्रिंट जैसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लिखित परीक्षा के आधार पर 1,74,317 अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया, जो 26 दिसंबर 2024 से 7 फरवरी 2025 तक चला। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) 10 फरवरी से 27 फरवरी 2025 तक हुई। इन सभी चरणों को पार करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई, जिसमें सामान्यीकरण (Normalization) और आरक्षण नीतियों का पालन किया गया।



रिजल्ट का ऐलान व खुशी का माहौल

13 मार्च 2025 को दोपहर 2 बजे रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बोर्ड ने सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक भी जारी किए। चयनित अभ्यर्थियों में से 24,102 अनारक्षित श्रेणी से, 6,024 ईडब्ल्यूएस से और बाकी अन्य आरक्षित वर्गों से हैं। यह परिणाम होली से ठीक पहले आया, जिसे योगी सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा उपहार बताया। सोशल मीडिया पर #BiggestUPPoliceJobDrive ट्रेंड करने लगा, और अभ्यर्थियों ने सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की तारीफ की।

सरकार और बोर्ड का दावा



बोर्ड अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने कहा, यह भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है। आधार सत्यापन, फिंगरप्रिंट, और कड़ी निगरानी ने प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया। योगी सरकार ने इसे अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती करार दिया है, जिससे युवाओं को रोजगार और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

अब चयनित अभ्यर्थियों को क्या करना होगा?

चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह खुशी का पल है, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। फाइनल रिजल्ट के बाद अब उन्हें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, जो इस प्रकार हैं -

चिकित्सा परीक्षण

चयनित अभ्यर्थियों को सबसे पहले मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। यह टेस्ट उनकी शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य की जाँच के लिए होगा। इसमें दृष्टि, सुनने की क्षमता, और अन्य स्वास्थ्य मानकों की जाँच की जाएगी। जो अभ्यर्थी इस टेस्ट में फेल होंगे, उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

दस्तावेजों की अंतिम जाँच

हालांकि दस्तावेज सत्यापन पहले हो चुका है, लेकिन नियुक्ति से पहले एक अंतिम जाँच होगी। अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाणपत्र (10वीं, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र आदि) तैयार रखने होंगे। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में चयन रद्द हो सकता है।

प्रशिक्षण की तैयारी

चयनित अभ्यर्थियों को 9 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने 4 फरवरी 2025 को घोषणा की थी कि यह प्रशिक्षण एक साथ शुरू होगा। प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण, कानून की जानकारी, और पुलिसिंग के गुर सिखाए जाएँगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाएगी।

ज्वॉइनिंग लेटर का इंतजार

मेडिकल टेस्ट और अंतिम जाँच के बाद अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। इसमें उनकी पोस्टिंग और प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर नजर रखें और कोई भी नोटिफिकेशन मिस न करें।

अभ्यर्थियों के सामने चुनौतियाँ

हालांकि यह सफलता का पल है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर चिंता जताई है। कई का कहना है कि मेडिकल टेस्ट में छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बाहर होने का डर है। एक अभ्यर्थी ने लिखा, लिखित और PET में पास होने के बाद भी मेडिकल में रिजेक्शन का खतरा बना रहता है। इसके अलावा, प्रशिक्षण की कठिनाई को लेकर भी चर्चा है।

कैमरे की नजर में होली

















कप्तान के साथ बरेली पुलिस की होली।



रंग में सराबोर संभल के कप्तान।













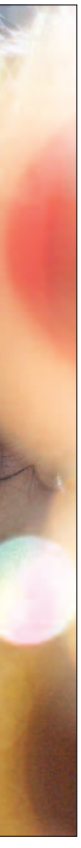












देश भर में रमजान के मौके पर रोजा इफ्तार का दौर भी चल रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की तरफ से आयोजित इफ्तार में धर्म गुरुओं के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शिरकत की। इस मौके पर पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप, राजेंद्र चौधरी, एमएलसी जासमीर अंसारी, विधायक रविदास महरोत्रा भी शामिल हुए। इस बीच बाजारों में भी ईद की तैयारियों की भीड़ देखी जा रही है। शहर के प्रमुख बाजार जैसे अमीनाबाद, नखास, चौक और रोजेदारों का नया डेस्टिनेश हुसैनाबाद नजर आ रहा है। जहां इफ्तार से लेकर सहरी तक ईद की खरीदारी के लिए काफी भीड़ उमड़ रही है।

बिहार फतेह की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी

अभिषेक रंजन

संघ प्रमुख बोले, विरासत बचाने के लिए न्यायालय है आपस में लड़ने की जरूरत नहीं

बिहार चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करना चाहती है

नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू के मुकाबले भाजपा के मंत्री ज्यादा



लखनऊ। 27 साल बाद दिल्ली फतेह करने के बाद भाजपा का अगला लक्ष्य बिहार और असम राज्य है, जहां पर इसी साल अक्टूबर और नवंबर में विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है। बीते 24 फरवरी को प्रधानमन्त्री ने बिहार के भागलपुर में किसानों के खाते में सम्मान निधि भेजी तो असम में जनजातिय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर दोनों ही राज्यों में चुनावी शंखनांद किया है। इधर बाबा बागेश्वर ने भी बिहार में अपने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर बिहार में छोटी-छोटी बैठकों के जरिए जनाधार जुटाने का काम तेज कर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर बिहार पर थे, इस दौरान उन्होंने जिले में लगने वाली शाखों को दोगुना करने और श्रंखला बना कर जोड़ने का आह्वान किया है।

21 मार्च से 23 मार्च तक बेंगलुरू में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने वाली है। इस बैठक में 1500 से 1600 प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। इस बैठक में भाजपा सहित संघ के सभी सहयोगी संगठन के पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में संघ 1 वर्ष के कामकाज की रूपरेखा तय की जाएगी। इस साल संघ के स्थापना के 100 साल पूरे हो गए है। ऐसे में इस बैठक में संघ अगले वर्ष के कार्यक्रमों के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाएगा। विजयादशमी 2025 से विजयदशमी 2026 तक संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाने वाला है। इस बैठक से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बेंगलुरू में होने वाले इस बैठक में बिहार चुनाव के संबंध में भी चर्चा होने वाली है। बिहार चुनाव से संबंधित सभी सहयोगी संगठनों को कैसे काम करना है इसके बारे में भी दिशा निर्देश तय किया जाएगा। बता दें कि बिहार दौरे से पहले संघ के के सरसंचालक मोहन भागवत पूर्वी भारत के प्रवास पर थे, बिहार से पहले वो 10 दिनों तक बंगाल प्रवास, 5 दिनों का असम प्रवास और चार दिनों के अरुणाचल प्रवास पर थे।

बिहार के अपने प्रवास पर आए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी स्वयंसेवक खुद से एक शृंखला बनाकर लोगों को संघ और शाखा से जोडें, शाखा का संचालन नियमित हो। पांच दिनों के प्रवास के दौरान सरसंघचालक ने उत्तर बिहार के मिथिला, तिरहुत और चंपारण क्षेत्र के प्रांत प्रमुख तक से संवाद किया। मोहन भागवत पांच दिनों के बिहार प्रवास के अंतिम दिन रविवार को अलग-अलग टोली के साथ समन्वय बैठक की।

संघ प्रमुख ने शाखा की संख्या व संचालन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शाखा की संख्या बढे, इसकी चिंता हर विभाग के पदाधिकारी को करनी चाहिए। शाखा से जुड़ने वाले स्वयंसेवकों की रुचि बनी रहे तथा संख्या बढे, इसके लिए थोड़ा बदलाव भी करना चाहिए। एक स्वयंसेवक की जिज्ञासा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर थी। इस पर मोहन भागवत ने कहा कि यह सरकार का काम है। जहां तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, हमारा हिन्दू समाज जनसंख्या को लेकर सजग है। हां, एक परेशानी यह है कि जिस भी परिवार में जनसंख्या का अनुपात दो व तीन से कम होगा, वहां इको मैनेजमेंट प्रभावित होता है। अगर किसी को एक संतान है, तो परिवार में वह चाचा किसे कहेगा, मौसी व बुआ किसे कहेगा। इसलिए हिन्दू समाज को चिंता करनी चाहिए कि हमारा सामाजिक अनुपात नीचे नहीं जाए। एक अन्य स्वयंसेवक की जिज्ञासा, प्राचीन विरासत के संरक्षण को लेकर थी। इस पर संघ प्रमुख ने कहा, हमारी विरासत बचाने के लिए देश में न्यायालय व अन्य संवैधानिक फोरम हैं। वहां पर अपनी बात को रखें। विरासत बचाने के लिए हिन्दुस्तानी को आपस में लड़ने-झगड़ने की जरूरत नहीं है।

मोदी का भागलपुर में कार्यक्रम

बीजेपी ने भागलपुर क्षेत्र ही क्यों चुना इसके भी क्षेत्रीय और जातीय मायने हैं। बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र की तर्ज पर अपर हैंड रहना चाहती है। जो हाल शिवसेना का हुआ है वहीं हाल जदयू का होगा ऐसा बीजेपी की रणनीति को देखते हुए लग रहा है। जहाँ जहाँ एनडीए में बीजेपी जूनियर पार्टनर थी वहां अब भाजपा सीनियर पार्टनर होती जा रही है। भाजपा की कोशिश है कि इस बार वह अपने दम पर ही बहुमत का आंकड़ा पार कर ले ताकि मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार पर यदि कोई डोरे डाले तो उससे भाजपा को चिंता करने की जरूरत न रहे। इसी महीने बिहार में नीतीश कुमार सरकार का विस्तार किया गया है। जिस के जरिए भाजपा अगड़ों, पिछड़ों और दलितों को साथ लेकर बहुमत हासिल करने में जुट गई है। अल्पसंख्यक समाज के लिए पूर्व केन्द्रीय मन्त्री शहनवाज हुसैन पर भी जिम्मेदारी संगठन ने दे रखी है। उधर कोर्ट ने राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव को एक मामले में कोर्ट में हाजिर होने का फरमान सुनाया है। जाहिर है कि यदि कोई आरोप लालू पर तय होता है तो बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार के मसले पर फायदा भाजपा को मिलेगा और नुकसान विपक्ष को होगा जैसा अभी दिल्ली के विधान सभा चुनाव में देखने को मिला है। भ्रष्टाचार के मसले पर दिल्ली की जनता ने लगातार दो बार सीएम रहे अरविंद



केजरीवाल से कुर्सी छीन ली है।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के भागलपुर दौरे के कई प्रकार के सियासी मायने हैं। इसका सामाजिक और धार्मिक असर के साथ 13 जिलों की विधान सभा सीटों पर जातीय और क्षेत्रीय प्रभाव पर भी नरेन्द्र मोदी असर डाल सकते हैं। प्रधानमन्त्री के भागलपुर दौरे का एक ओर जहां किसानों को बड़ी सौगात दी है, तो वहीं यहाँ एनडीए को 59 विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। भागलपुर भाजपा और एनडीए का मजबूत गढ़ रहा है।

भागलपुर की पहचान बिहार के लिए आजादी के बाद राज्य में हुए सबसे बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे वाले क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत कुल 59 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें 40 सीटों पर मौजूदा समय में एनडीए के विधायक हैं। सिर्फ 19 विधानसभा सीटों पर ही पिछले चुनाव में प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को जीत मिली थी। भागलपुर जिले में 7 में से 5 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, वहीं मुंगेर में बांका, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार में 4 और अररिया में 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। वहीं किशनगंज में एक भी सीट एनडीए नहीं जीत पाई थी। भागलपुर को देश में सिल्क सिटी के तौर पर जाना जाता है लेकिन वर्ष 1989 में हुए दंगों ने इसे बिहार में आजादी के बाद हुए सबसे बड़े हिंदू मुस्लिम दंगों वाला क्षेत्र भी बनाया। रिपोर्टों के अनुसार दंगों में करीब 48 हजार लोग प्रभावित हुए। जस्टिस शमसुल हसन और आरएन प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दंगे में 852 लोग मारे गए थे, 524 लोग घायल हुए थे, 11 हजार 500 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। 600 पावर लूम 1700 हैंडलूम क्षतिग्रस्त हुए थे। इन्हीं दंगों ने बिहार के मुसलमानों का मोह कांग्रेस से तोड़ा और लालू यादव का एमवाई यानि मुस्लिम यादव समीकरण बना जिससे वे बिहार में बड़े सियासी सफलता हासिल करते रहे। सीमांचल कोसी और अंग के इलाके में भागलपुर से प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी का संदेश खास प्रभाव डाल सकता है। सीमांचल के जिलों को जहां सर्वाधिक मुस्लिम बहुल इलाकों में माना जाता है। वहीं कई प्रकार की चुनौतियों को झेलते बिहार के इस इलाके में पलायन और पिछड़ापन बड़ी समस्या है। इन तमाम चीजों को चुनाव में भुनाने के एक बड़ी कोशिश अब पीएम मोदी के दौरे से हो सकती है। ●

बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के क्या मायने हैं

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पिछले कुछ दिनों के दौरान दो बार बिहार आ चुके हैं। यहां उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर एकजुटता का संदेश दिया। इस साल पहली बार बिहार की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने एक मंच से कई संदेश दे दिए। भागलपुर में पीएम किसान सम्मान समारोह के मंच पर मौजूद मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार की प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने तारीफ करते हुए जहां लाडला मुख्यमन्त्री बताया वहीं मुख्यमन्त्री ने भी प्रधानमन्त्री की तारीफ करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी। कार्यक्रम के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नडडा ने बिहार में मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की, इस योजना के तहत 8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इस मौके पर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज बिहार के 75 लाख से अधिक परिवार के किसानों के खाते में 1600 सौ करोड़ से अधिक रुपये दिए गए। हर किसान के खाते में किसान निधि की किस्त एक क्लिक पर गई है। एनडीए सरकार चाहे केन्द्र में हो या फिर बिहार में हो। किसान कल्याण हमारी पहली प्राथमिकता है, बीते दशक में हमने पूरी शक्ति से काम किया है। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है। जिससे खेतीबारी से जुड़े उनके खर्चों में मदद मिल सके। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वह कभी भी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं। एनडीए सरकार ने इसे बदला है। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था। यूरिया की कालाबाजारी होती थी आज देखिए किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। आप कल्पना कीजिए अगर एनडीए सरकार न होती तो क्या होता। अगर एनडीए सरकार नहीं होती तो आज भी हमारे किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। आज भी बरौनी कारखाना बंद रहता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बीते सालों में भारत का कृषि निर्यात बहुत बढ़ा है। इसलिए किसानों को उत्पाद की ज्यादा कीमत मिल रही है। अब बिहार के मखाना की बारी है, मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग बन चुका है। मैं 365 दिन में से 300 दिन मखाना खाता हूँ। यह सुपरफूड है इसलिए इस बार के बजट में मखाना बोर्ड बनाने का एलान किया गया है।



रिलायंस को झटका

2 हजार करोड़ रुपये सरकार ने मांगे

केजी बेसिन गैस विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

शबीह अहमद रिज़वी

नई दिल्ली। कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन के एक दशक पुराने गैस रिसाव विवाद में केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके साझेदारों से 2.81 अरब डॉलर (लगभग 23,000 करोड़ रुपये) की वसूली का आदेश दिया है। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद सुर्खियों में आया है, जिसमें कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया। यह विवाद न केवल भारत के तेल और गैस क्षेत्र की जटिलताओं को उजागर करता है, बल्कि देश की सबसे बड़ी निजी कंपनियों में से एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। इस रिपोर्ट में हम इस मामले की पूरी कहानी, इसके कानूनी पहलुओं और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं।

कहां से हुई विवाद की शुरुआत

यह विवाद 2013 में शुरू हुआ, जब सरकारी तेल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर गंभीर आरोप लगाए। ओएनजीसी का दावा था कि रिलायंस के KG-D6 ब्लॉक में उसके पड़ोसी गैस ब्लॉक से गैस बहकर जा रही थी। ओएनजीसी के अनुसार, यह रिसाव प्राकृतिक नहीं था, बल्कि रिलायंस ने जानबूझकर इसका फायदा उठाया। ओएनजीसी का कहना था कि उसके ब्लॉक से लगभग 18 अरब क्यूबिक मीटर गैस रिलायंस के ब्लॉक में चली गई, जिससे रिलायंस को अनुचित लाभ हुआ।

रिलायंस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कंपनी का तर्क था कि गैस का यह प्रवाह प्राकृतिक रूप से हुआ और यह दोनों ब्लॉकों के बीच भूगर्भीय संरचना के कारण संभव था। रिलायंस ने यह भी कहा कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) के तहत उसे किसी तरह का मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओएनजीसी ने इसे अवैध दोहन करार देते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।

इस विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में अमेरिकी फर्म DeGolyer and MacNaughton डी एंड एम को जांच के लिए नियुक्त किया। 2016 में डी एंड एम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पुष्टि हुई कि ओएनजीसी के ब्लॉक से करीब 11.832 अरब क्यूबिक मीटर गैस रिलायंस के KG-D6 ब्लॉक में चली गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह रिसाव 2009 से 2013 के बीच हुआ और रिलायंस ने इस गैस का उत्पादन कर लाभ कमाया। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने नवंबर 2016 में रिलायंस और उसके साझेदारों - बीपी (ब्रिटिश पेट्रोलियम) और निको रिसोर्सेज - से 1.55 अरब डॉलर की मांग की। यह राशि उस गैस की कीमत और ब्याज के रूप में तय की गई थी, जो कथित तौर पर ओएनजीसी से रिलायंस के पास गई। सरकार का कहना था कि यह राशि रिलायंस को अनुचित लाभ के रूप में मिली थी, जिसे वापस करना होगा।

शेयर बाजार पर असर

इस खबर का असर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर भी देखा गया। 4 मार्च 2025 को कंपनी के शेयर 1,172 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर कारोबार कर रहे थे, लेकिन इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद लंबा खिंचने पर रिलायंस की वित्तीय स्थिति और निवेशकों के भरोसे पर असर डाल सकता है। हालांकि, कंपनी की मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे अभी बड़ा झटका नहीं माना जा रहा। ●

रिलायंस करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख

रिलायंस ने सरकार की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। कंपनी ने तर्क दिया कि गैस का प्रवाह प्राकृतिक था और इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। रिलायंस ने मामले को अंतरराष्ट्रीय पंचाट (Arbitration) में ले जाने का फैसला किया। 2018 में पंचाट ने रिलायंस के पक्ष में फैसला सुनाया। पंचाट का कहना था कि सरकार का दावा तकनीकी रूप से सही नहीं है और रिलायंस को कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। इस फैसले से रिलायंस को बड़ी राहत मिली, लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी। सरकार ने पंचाट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फरवरी 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पंचाट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि रिलायंस ने अनुचित लाभ उठाया और गुप्त तरीके से ओएनजीसी की गैस का दोहन किया। कोर्ट ने माना कि रिलायंस ने ओएनजीसी के संसाधनों का इस्तेमाल कर मुनाफा कमाया, जो PSC के नियमों के खिलाफ था। इस फैसले के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रिलायंस और उसके साझेदारों से 2.81 अरब डॉलर की वसूली का नया आदेश जारी किया। यह राशि पिछले 1.55 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें नए आकलन, ब्याज और कानूनी खर्च शामिल किए गए हैं। कोर्ट के इस फैसले ने मामले को फिर से गरमा दिया और रिलायंस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दीं।

क्या कहा रिलायंस ने

रिलायंस ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को अस्थिर और गलत करार दिया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसे इस मामले में किसी देनदारी की उम्मीद नहीं है और वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। रिलायंस का कहना है कि गैस रिसाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि PSC में ऐसी स्थिति के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जो उसे मुआवजा देने के लिए बाध्य करे। रिलायंस ने अपने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि वह इस कानूनी लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेगी।

भानवी सिंह ने लक्जरी लाईफ जीने के लिए राजा भैय्या से मांगा गुजारा भत्ता

टीएनसी ब्यूरो

लखनऊ। जनसत्ता दल लोकतान्त्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैय्या और उन की पत्नी के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अदालत में भानवी सिंह ने 100 करोड़ रुपये और गुजारे भत्ते के रूप मे हर माह 25 लाख रुपये की माँग की है, ताकि वो राजशाही रहन सहन के साथ अपनी जिन्दगी गुजार सकें। इस मामले पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैय्या तो कुछ नहीं बोले लेकिन छाया की तरह उन के साथ रहेने वाले पूवं साँसद अक्षय प्रताप सिंह ने भानवी सिंह पर निशान साधा है, अक्षय प्रताप कहते हैं, कि घर की बात घर में ही रहती तो अच्छा होता, लेकिन घर की बात को बाहर लाया कौन, घर की बात को मसालेदार गॉसिप बनाकर लोगों के बीच परोसने वाली भानवी सिंह का असली चेहरा आप लोगों के सामने लाना आवश्यक है, और ये सिलसिला जारी रहेगा।

वो कहते हैं, कि भइया तो इस विषय पर कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जिस तरह से भानवी सिंह विष वमन कर राजा भइया की छवि



धूमिल करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाये हैं, कोई भी पत्नी अपने पति के लिए कभी भी ऐसा न कहेगी न लिखेगी, उनके इसी व्यवहार के कारण भइया 10 वर्षों से अधिक से उनसे अलग ही रह रहे हैं।

1995 में भइया से विवाह होने के बाद भानवी सिंह को भदरी से चल- अचल अकूत संपत्ति दी गयी, जिसमें प्रतापगढ़ में खेत, बाग, दिल्ली में शानदार बंगला, उत्तराखंड में विशाल सेब के बाग और ज़मीन, साथ ही वे दो व्यापारिक संस्थान की मालकिन बनीं, आभूषणों, गहनों की तो कोई गिनती ही नहीं है। उन्हें इतनी संपत्ति मिली की उनकी संपदा राजा भइया से अधिक हो गयी। कई वर्षों से वे राजा भइया से अधिक आयकर रिटर्न भरती हैं। इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने अदालत से राजा भइया के जैसी जीवनशैली जीने के लिए और अपने साज श्रृंगार के लिए महंगे विदेशी ब्रांड खरीदने के लिए राजा भइया से '10 लाख' प्रति माहकी मांग की थी। फिर कुछ दिनों पहले उन्हें लगा कि ये रकम उनके शौक पूरा करने के लिए बहुत कम हैं और उन्होंने अपनी मांग बढ़ा कर '100 करोड़' रुपये और साथ में ही '25 लाख' रुपये प्रति माह भइया से अदालत के माध्यम से मांगे। ऐसे में बात कैसे बनेगी। क्योंकि एक तरफ वो तलाक देने से इनकार कर रही हैं और बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिशों के लिए उन्होंने दरवाजे बन्द कर रखे हैं।



कैंसर वैज्ञानिक डॉ. अदिरिया ने बढ़ाया मान

लखनऊ की बेटी अमेरिका में सीईआई ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित

लखनऊ। कैंसर वैज्ञानिक डाक्टर अदिरिया हसन, जो विश्व प्रसिद्ध फॉक्स चेस कैंसर सेंटर, फिलाडेल्फिया, अमेरिका में पोस्टडॉक फेलो हैं, को फिलाडेल्फिया में वार्षिक समारोह में प्रतिष्ठित कैंसर एपिजेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के सी डेविड एलिस ट्रैवल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। डाक्टर अदिरिया हसन पिछले तीन वर्षों से फॉक्स चेस कैंसर सेंटर में कैंसर पर अपना शोध कर रही हैं। पिछले वर्ष उन्हें फॉक्स चेस फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था।

डाक्टर अदिरिया ने हसन ने इंटीग्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से पीएचडी पूरी करने के बाद कैंसर के क्षेत्र में आगे अनुसंधान करने के लिए अमेरिका गई थीं। उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से बायोटेक्नोलॉजी में एम.टेक भी किया था। प्रसिद्ध कैंसर वैज्ञानिक सी डेविस एलिस के नाम पर स्थापित सीईआई पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अनुसंधान के लिए अमेरिका और विदेश में यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है। 6 मार्च को फिलाडेल्फिया में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में वार्षिक कार्यक्रम में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अपने काम को साझा करने और नवीनतम खोजों के बारे में अधिक जानने के लिए स्वागत किया गया, जो एपिजेनेटिक्स को रोगी देखभाल के अग्रभाग में लाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का एक प्रमुख लक्ष्य विश्व स्तरीय विज्ञान को किसी भी शैक्षिक स्तर पर वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाना था। संगोष्ठी में जीन विनियमन से लेकर 3डी जीनोम से लेकर उम्र बढ़ने और चिकित्सा विज्ञान तक के विषयों पर चर्चा हुई। पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता क्लो अज़ादेगन, मिल्ली कॉम्ब्स, ऐडन डगलस, धर्मेंद्र कश्यप (भारत), रेबेका स्मिथ और मार्टिन वाल्श थे। संगोष्ठी का मुख्य भाषण एनी ब्रून्नेट, पीएचडी, मिशेल और टिमोथी बराकेट, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न प्रोफेसर, और रॉबर्ट किंग्स्टन, पीएचडी, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में मुख्य शैक्षणिक अधिकारी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में आनुवंशिकी के प्रोफेसर द्वारा दिया गया था। डाक्टर अदिरिया हसन देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मसुदुल हसन की बेटी हैं।



सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तरी : (GS/GK NCERT) प्रतियोगी परीक्षाओं में दिला सकती है सफलता

GS-NCERT के लिए लखनऊ में एक मात्र संस्थान GS अकादमी कपूरथला लखनऊ ...

1. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है?
A.कोयली - गुजरात B.नागपट्टीनम - आन्ध्र प्रदेश
C.नुमालीगढ़ - असम D.मनाली - तमिलनाडु

2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक उंचाई वाली चोटी कौन - सी है ?
A.सौडिल पीक B. माउंट थुइल्लर
C.माउंट दियावालो D. माउंट कोयल

3. बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ?
A.हिमाचल प्रदेश B. जम्मू-कश्मीर
C.सिक्किम D. उत्तराखंड

4. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
A.सरदार सरोवर बाँध - नर्मदा नदी
B. तिलैया बाँध - कोणार नदी
C.गांधी सागर बाँध - चम्बल नदी
D. नागार्जुन बाँध - कृष्णा नदी

5. तपोवन और विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है ?
A.मध्य प्रदेश B. उत्तर प्रदेश
C.उत्तराखंड D. राजस्थान

6. भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है ?
A. उष्णकटिबंधीय अवस्थिति B. समुद्र के निकट होना
C.पश्चिमी घाट D. हिमालय

7. निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है ?
A. ओडिशा में नंदन कानन B.असम में काजीरंगा
C.प. बंगाल में सुंदर वन D.प. बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, शिवपुर

8. मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं -
1. समोच्च क्षेत्र की किनारा बंदी
2. भू-उपयोग का विनियमन
3. वृक्षों की कटाई
A. 1 व 3 B. 1 व 2
C. 2 व 3 D. 3 व 4

9. निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है ?
A. उत्तर प्रदेश B. बिहार
C.मध्य प्रदेश D. महाराष्ट्र

10. निम्नलिखित में कौन - सा कथन असत्य है ?
A. एन्थ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है
B.भारत में पाया जाने वाला अधिकाँश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है
C.जम्मू-कश्मीर में एन्थ्रासाइट कोयला पाया जाता है
D. भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78ए पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है

11. सूची -द्य को सूची ढ्ढ से सुमेलित कीजिये
सूची I (जनजाति) A. टोडा B. लेप्चा C. बिरहोर D.गारो
सूची II (क्षेत्र) 1.सिक्किम 2. मेघालय 3. तमिलनाडू 4. झारखण्ड
कूट -
A. A- 3, B - 2, C - 1, D - 4
B. A - 3, B - 1, C - 4, D - 2
C. A - 2, B - 3, C - 4, D - 1
D. A - 4, B - 2, C - 1, D - 3

12. भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरिकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए
1. पश्चिम बंगाल 2. तमिलनाडू
3. महाराष्ट्र 4. गुजरात
A. 1,2,3,4 B. 2 3 4 1
C.3 4 2 1 D. 4 3 2 1.

13. निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GDP) का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है?
A. कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से
B. रक्षा तथा लोक प्रशासन से
C.सेवा क्षेत्र से
D. विनिर्माण , निर्माण, बिजली तथा गैस से

14. निम्न में से कौन-सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है ?
A. मूल्य सूचकांक B. थोक मूल्य सूचकांक
C.उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
D.औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक

15. भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है ?
A. मध्य प्रदेश B. आंध्र प्रदेश
C.कर्नाटक D. राजस्थान

16. भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं
A. आंध्रप्रदेश प्रदेश एवं महाराष्ट्र B. पंजाब एवं हरियाणा
C.पंजाब एवं उ.प्र. D.उ.प्र. एवं आंध्रप्रदेश.

17. मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है ?
A. रबी फसल B. नकदी फसल
C.खरीफ फसल D.इनमे से कोई नहीं

18 घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
A. करों की कमी B. मजदूरी में बढ़ोतरी
C.मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी D. मुद्रा आपूर्ति में कमी

19. राज कमेटी किससे सम्बन्धित थी?
A. कृषि से B. वृहत उद्योगों से
C.लघु उद्योग से D.बैंकिंग से

20. निम्नलिखित में से कौन-भारत निर्माण का अंग नहीं है ?
A. ग्रामीण आवास B. ग्रामीण विद्युतीकरण
C.कृषि आधारित उद्योग D.ग्रामीण टेलीफोनी

21 निम्नलिखित में से किसने सवयं को हिन्दुस्तान का तोता कहा था?
A. मालिक मुहम्मद जायसी B. रसखान

C.अमीर खुसरो D.अमीर हसन

22. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए -

सूची-I A. भरतनाट्यम B. कुचिपुडि C. कथकली D. ओडिशी

सूची-II 1. ओडिशा 2. केरल 3. आंध्र प्रदेश 4. तमिलनाडु

A. A - 4, B- 3, C - 2, D - 1

B. A - 3, B - 4, C - 1, D - 2

C. A - 2, B- 3, C - 4, D - 1

D. A - 1, B- 2, C - 3, D - 4

23 निमंलिखित युग्मो पर विचार कीजिये-

1. गरबा - गुजरात 2. मोहिनीअट्टम - ओडिशा

3. यक्षगान-कर्नाटक

उपर्युक्त युग्मो में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2 और 3

C.केवल 1 और 3 D. 1,2 और 3

24. रणजीत सिंह (1792-1839) ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रमानुसार सजाइए-

1. लाहौर 2. अमृतसर 3. कांगड़ा 4. कश्मीर

A. 1-2-3-4 B. 1-2-4-3

C.2-1-3-4 D. 4-3-2-1

25. भारत में उपनिवेशी शासनकाल में 'होम चार्जेज' (Home charges) भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था । निम्नलिखित में से कौन-सी निधि/ निधियाँ होम चार्जेज की संघटक थी/थीं ?

1. लंदन में इण्डिया ऑफिस के भरण-पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि

2. भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि

3. भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2

C.केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

26. 1836-40 के दौरान मालाबार में जान्मी (हिन्दू जमींदारों) के विरुद्ध मोप्पिलों मोपिलाओं (मुस्लिम किसानों) के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?

A. सैय्यद अली व उसका पुत्र फजल अली

B. दिगम्बर विश्वास व विष्णु विश्वास

C. मजनूशाह व चिराग अली शाह

D. इनमें से कोई नहीं

27. निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था?

1. जनरल जॉन निकलसन 2. जनरल नील 3. मेजर जनरल हैवलॉक 4. सर हेनरी लारेंस

A. 1, 2 और 3 B. 1, 3 और 4

C.2, 3 और 4 D. इनमें सभी

28. इण्डिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे

A. मौलाना अबुल कलाम आजाद B. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

C.नरेन्द्र देव ष्ठ.आशफ अली

29. दी मैन हू डिवाइडेड इण्डिया पुस्तक के लेखक थे

A. मौलाना अबुल कलाम आजाद B. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

C.रफीक जकारिया D. लैरी कॉलिन्स ओर डोकिनिक लापियेर

30. कथन (A) : हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण (R): हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया

A. A और R दोनों सही है तथा R, A की सही व्याख्या करता है

B. A और R दोनों सही है किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है

C.A सही है और R गलत है

D.R सही है और A गलत है

31. निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे ? नीचे दिये कूट से सही उत्तर चुनिए : 1, कोरकै 2. पुहर 3. तोपडी 4. मुशिरि

A. 1 और 2 B. 2 और 3

C.3 और 4 D.4 और 1

32. किसके शासनकाल में डायमेक्स/डीमेकस भारत आया था ?

A. चन्द्रगुप्त मौर्य B. बिन्दुसार

C.अशोक D.कनिष्क

33. निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया ?

A. चौथी B. पांचवीं

C.छठी D.आठवीं

34. राज्य सभा का अध्यक्ष (सभापति) -

A. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है

B. संसद द्वारा चयनित होता है

C. उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है

D.राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है

35. अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन - सा अधिकार है ?

A. विधायी B. प्रशासनिक

C. न्यायी D.वैयक्तिक

36. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है ?

A. अनुच्छेद 50 क B. अनुच्छेद 50 ख

C. अनुच्छेद 51 क D.अनुच्छेद 51 ख

37. भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिये

1.भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना

2. ग्राम पंचायतों को संघटित करना

3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहित करना

4. सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना इनमें से कौन से गाँधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिम्बित होते हैं

A. 1,2,4 B. 2,3

C. 1,3,4 D.1,2,3,4

38. समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ हैं

1. अनुच्छेद 13 2. अनुच्छेद 14

3. अनुच्छेद 15 4. अनुच्छेद 16

कूट-----

A. 1 और 2 B. 1,2,3

C. 2,3,4 D.सभी चारों

39. नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं

1. जन्म 2. आनुवंशिकता

3. पंजीयन द्वारा 4. अनुरोध द्वारा

A. 1,2 B. 1,2,3

C. 2,3 D.2,3,4

40. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं

A. 365 B. 375

C. 315 D.335

41. भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची किससे संबंधित है ?

A. दल-बदल कानून B. संघ की भाषाएँ

C. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा D.इनमें से कोई नहीं

42. भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है ?

A. भाग-1 में B. भाग-4 क में

C.भाग-2 में D.भाग-4 में

43. विधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन - सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है ?

A. सामाजिक न्याय B. राजनीतिक न्याय

C. विचार की स्वतंत्रता D.पूजा की समानता

44. डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं ?

A. तानिका शोध B. मस्तिष्काघात

C.हंटिंगटन रोग D.अल्जाइमर रोग

45. निम्नलिखित में से कौन-सा एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन है?

A. वैसोप्रोसिन B. ऑक्सीटोसीन

C.ए.सी.टी.एच D.कोर्टीसोन

46नेचुरल सलेक्शन द्वारा ऑरिजन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी ?

A. चार्ल्स डार्विन B. चार्ल्स डिकेंस

C.ह्यूगो डी. ब्रिज D.लैमार्क

47. यह कम्प्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नही सकता

A. हार्डवेयर B. प्रिंटर

C.माउस D.सॉफ्टवेर

48. कम्प्यूटरों के सन्दर्भ में सॉफ्टवेर का क्या अर्थ है

A. फ्लोपी डिस्क B. कम्प्यूटर प्रोग्राम

C.कम्प्यूटरसरकिट्री D.ह्यूमन ब्रेन

49. निम्न में कौन सा सौर उर्जा का स्त्रोत है

A. नाभकीय विखंडन B. नाभकीय संलयन

C.कृत्रिम रेडियोधर्मिता D.एक्स किरण उत्सर्जन

50. निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमानका दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है

A. चार्ल्स का नियम B. बॉयल का नियम

C. डॉल्टन का नियम D. ग्राहम का नियम



"G.S.अकादमी"

Committed To Your Success....

+91-9473893577

''करें GS-NCERT की तैयारी''

GS अकादमी के साथ...

उत्तर :

1-B, 2-A, 3-B, 4-B, 5-C, 6-A, 7-D, 8-B, 9-C,
10-D, 11-B, 12-B, 13-C, 14-B, 15-D, 16-B,
17-C, 18-C, 19-A, 20-C, 21-C, 22-A, 23-C,
24-A, 25-D, 26-A, 27-C, 28-B, 29-C, 30-A,
31-C, 32-B, 33-B, 34-C, 35-A, 36-C, 37-B,
38-C, 39-B, 40-D, 41-A, 42-A, 43-D, 44-D,
45-A, 46-A, 47-D, 48-B, 49-B, 50-B



डिस्पैगिया

की समस्या होने पर खाना निगलने में होती है परेशानी

समय पर इलाज है बेहद जरूरी

खांसी और कफ की समस्या होने पर गले में दर्द होना आम बात है। कफ होने पर गले की मांसपेशियों पर दबाव पड़ने की वजह से गले में दर्द हो सकता है। वहीं मौसम में बदलाव होने की वजह से भी गले में खराश हो जाती है, जिससे गले में दर्द हो जाता है। मेडिकल की भाषा में इस समस्या को डिस्फेजिया कहा जाता है। इसमें गले की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। यह समस्या होने पर कुछ भी खाने पर गले में दर्द होता है। वहीं समय रहते इस समस्या पर ध्यान न देने से यह समस्या अधिक बढ़ सकती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह स्थिति क्यों होती है और इसके होने के क्या कारण होते हैं।

डिस्फेजिया क्या है

यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जिसमें खाना निगलने में परेशानी होती है। यह समस्या ठोस और पेय दोनों को निगलने में होती है। डिस्पैगिया में हमेशा गले में दर्द नहीं रहता है, लेकिन यह समस्या पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को परेशानी कितनी है। वहीं अगर समय रहते इस समस्या को कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो यह डिहाइड्रेशन, मालन्यूट्रिशन और निमोनिया का कारण बन सकता है।

कितने प्रकार के होते हैं डिस्फेजिया

ऑरोफरीन्जियल डिस्फेजिया

यह अक्सर गले को प्रभावित करने वाली मसल्स या न्यूरोलॉजिकल से जुड़ी समस्या हो सकती है। यह समस्या तब होती है, जब व्यक्ति द्वारा कुछ भी खाने या पीने पर खाना गले की नली से नीचे नहीं आ पाता है।

एसोफेजियल डिस्फेजिया

एसोफेजियल डिस्फेजिया की समस्या होने पर खाना निगलने के बाद चिपकने या ग्रासनली में फंसने जैसा एहसास होता है। इसोफेगस से जुड़ी किसी भी परेशानी की वजह से यह समस्या हो सकती है।

न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर

न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे स्ट्रोक या ब्रेन में चोट लगने पर डिस्फेजिया हो सकता है। इन समस्याओं के होने पर गले से जुड़ी मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा पार्किसन रोग या किसी भी तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने पर भी डिस्फेजिया हो सकता है।

मसल्स से जुड़ी समस्याएं

स्क्लेरोडर्मा या फिर मायस्थेनिया ग्रेविस की वजह से भी डिस्फेजिया की समस्या हो सकती हैं। इसकी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती हैं, जोकि खाना निगलने वाली मांसपेशियों से भी जुड़ी होती है। स्क्लेरोडर्मा में इसोफेगस के टिशूज हार्ड होने लगते हैं और सूजन आने लगती है। इसकी वजह से भी डिस्फेजिया का खतरा हो सकता है।

इसोफेगस से जुड़ी समस्या

बता दें कि इसोफेगस में इंफ्लेमेशन होने पर व्यक्ति को कुछ भी खाने में समस्या हो सकती हैं। वहीं इसोफेगस कैंसर या गले से जुड़े संक्रमण में भी डिस्फेजिया का खतरा हो सकता है।



रेस्पिरेटरी इश्यूज में लाभकारी माना जाता है तुलसी का सेवन



वैसे तो हम सभी के घर में तुलसी का पौधा होता है। वहीं तुलसी अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है और हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। वैसे तो लोग हर मौसम में तुलसी का सेवन करते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। क्योंकि ठंड के मौसम में जिद्दी खांसी से लेकर कंजेशन जैसी कई तरह की सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज को दूर करने में तुलसी बहुत कारगर मानी जाती है। सं मण से लड़ने से लेकर बलगम को साफ करने तक में तुलसी कई तरह से लाभकारी मानी गई है। तुलसी में एंटी-ऑक्सिडेंट, एसेंशियल ऑयल और कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर रखते हैं। ऐसे में आप तुलसी को अपनी डाइट में कई तरीके से शामिल कर सकते हैं। इससे आपको काफी आराम मिल सकता है।

रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होगा दूर

तुलसी में सिनेओल, यूजेनॉल और कैंफीन जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं। तुलसी में एंटी-फंगल, एंटी-बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। यह रेस्पिरेटरी इंफेक्शन को दूर करने में सहायक होते हैं। अगर आपको सामान्य सर्दी, फ्लू या गले में खराश की शिकायत है, तो आपको तुलसी का सेवन करना चाहिए। यह साइनसाइटिस, तुलसी ब्रोंकाइटिस और मौसमी फ्लू जैसे इंफेक्शन से लड़ने में सहायक होता है।

कफ की समस्या होगी दूर

तुलसी के सेवन से नेचुरली तरीके से कफ दूर होता है। ऐसे में अगर आपको सर्दी में खांसी-जुकाम की समस्या है, तो आपको तुलसी का सेवन करना चाहिए। दरअसल, तुलसी बलगम को पतला करने में मदद करता है, जिससे यह आसानी से बाहर निकल जाता है। वहीं इस तरह से आपका एयरवे भी आसानी से साफ हो जाता है।

इम्यूनिटी

तुलसी में विटामिन सी, एंटी-ऑक्सीडेंट और जिंक पाया जाता है। जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। वहीं तुलसी में एडाप्टोजेनिक गुण पाए जाते हैं, जो शरीर के तनाव को मैनेज करने में मदद करता है। क्योंकि तनाव न सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम पर बुरा असर डालता है, बल्कि यह रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए भी ट्रिगर साबित हो सकता है। ऐसे में तुलसी का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सांस से जुड़ी समस्याओं का भी कम सामना करना पड़ता है।



कंजेशन से राहत

सर्दियों के मौसम में कंजेशन की समस्या हो जाती है। ऐसे में तुलसी का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। तुलसी में एसेंशियल ऑयल मौजूद होता है, जो कंजेशन को कम करता है और साइनस के दबाव से भी राहत मिलती है। कंजेशन से राहत पाने के लिए तुलसी की चाय का भी सेवन किया जा सकता है। या फिर आप तुलसी के पत्तों को उबालकर भाप लें। इससे आपको जल्द ही आराम मिलेगा।

इन लोगों को भूल से भी नहीं खाना चाहिए आंवला

आंवला का सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आंवला का सेवन हर किसी के लिए लाभदायक नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें आंवला खाने से बचना चाहिए।



अगर आपका ब्लड शुगर कम है

आंवला आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और इसलिए इसे डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है या अगर आप पहले से ही मधुमेह की दवा ले रहे हैं, तो आंवला आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। इसका बहुत ज्यादा सेवन आपके शुगर लेवल को बहुत तेजी से गिरा सकता है, जिससे आपको चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है।

अगर आपको किडनी की समस्या है

जिन लोगों को पहले से ही किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें भी आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल, आंवला ऑक्सालेट से भरपूर होता है, जो किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। अगर आपको पहले कभी पथरी हुई है या उसका रिस्क है, तो आंवले के सेवन से बचें। खासतौर से, इसे कच्चा या जूस के रूप में बिल्कुल भी ना लें।

यदि ब्लड थिनिंग की दवा ले रहे हैं

आंवला तब आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, जब आप पहले से ही ब्लड थिनिंग की दवा ले रहे हैं। आंवला खून पतला करने वाली दवा के रूप में काम कर सकता है। इसलिए, अगर आप वारफेरिन या एस्पिरिन जैसी दवाएं ले रहे हैं, तो आंवला लेने से अत्यधिक रक्तस्राव या चोट लगने का जोखिम बढ़ सकता है।



बीएफआई 'मौलिक' कर्तव्यों को पूरा करने में विफल

'मुक्केबाजी के लिए तदर्थ समिति की जरूरत'

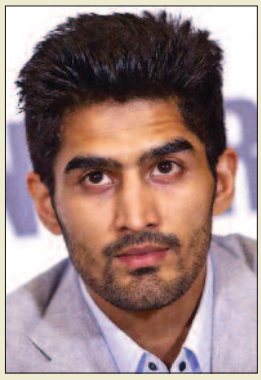
नयी दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की प्रमुख पीटी उषा ने मुक्केबाजी के लिए तदर्थ समिति नियुक्त करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महासंघ पिछले एक साल में अपनी 'मौलिक जिम्मेदारियों' को पूरा करने में विफल रहा है और 'व्यवस्था को बहाल करने तथा उचित प्रशासन सुनिश्चित करने' के लिए उनका यह कदम जरूरी था। उषा का यह बयान आईओए के उपाध्यक्ष गगन नारंग के 28 फरवरी के पत्र के जवाब में आया है। पूर्व ओलंपिक कांस्य विजेता निशानेबाज ने उन पर 'मनमाने' आदेश जारी करने और खिलाड़ियों के कल्याण को कम करने का आरोप लगाया था।

नारंग आईओए कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। आईओए के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजूद उषा अपनी रुख पर का दृढ़ता से कायम है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने आईओए से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। उषा ने नारंग को भेजे जवाब में कहा, ''...आपके (नारंग) इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि इस निर्णय या मेरी ओर से किसी कथित मनमानी कार्रवाई के कारण खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है। तदर्थ समिति नियुक्त करने का निर्णय मनमाना नहीं था, बल्कि व्यवस्था बहाल करने, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने और खिलाड़ियों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए एक आवश्यक कदम था।''

उन्होंने कहा, ''दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि बीएफआई पिछले वर्ष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने सहित अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा है।'' उन्होंने कहा, ''एशियाई खेल (2026) नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में नयी प्रतिभाओं की पहचान करने, होनहार मुक्केबाजों का चयन करने और भारत की पदक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण या अभ्यास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बहुत कम या कोई प्रयास नहीं किया गया है।''

उषा लंबे समय से कई मुद्दों पर कार्यकारी परिषद के सदस्यों के साथ विवाद में रही हैं। उन्होंने कार्यकारी परिषद के सदस्यों पर भारतीय खेलों की समग्र भलाई के बजाय 'व्यक्तिगत प्राथमिकताओं' को तरजीह देने का आरोप लगाया है। नारंग ने उन्हें पत्र लिखकर बीएफआई के संचालन के लिए तदर्थ समिति बनाने के उनके 'मनमाने' फैसले को वापस लेने की मांग की थी। इस पूर्व निशानेबाज ने कहा था, ''ऐसे मनमाने आदेश के कारण हमारे खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमें घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा रहा है'' आईओए ने 24 फरवरी को देश में मुक्केबाजी के मामलों की देखरेख के लिए पांच सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया था। आईओ एक का आरोप है कि बीएफआई समय पर राष्ट्रीय महासंघ का चुनाव कराने में विफल रहा। बीएफआई ने आईओए के फैसले को 'अवैध' करार दिया और आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। नारंग ने यह भी दावा किया कि बीएफआई के संचालन के लिए तदर्थ समिति बनाने का उषा का फैसला 'आईओए की कार्यकारी समिति के परामर्श या अनुमोदन के बिना' किया गया था। ●

मैं खुद चुनाव लड़ने को तैयार हूं : विजेंदर



ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले और एकमात्र पुरुष मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के जल्द से जल्द नए सिरे से चुनाव कराने की अपील करते हुए कहा कि अगर मौका मिला तो वह चुनाव लड़ने में संकोच नहीं करेंगे। बीजिंग ओलंपिक 2008 के कांस्य पदक विजेता 39 वर्षीय विजेंदर अभी पेशेवर सर्किट में खेल रहे हैं हालांकि उन्होंने 2022 के बाद से कोई मुकाबला नहीं लड़ा है। विजेंदर ने कहा, ''जब भी चुनाव हों, मैं उनमें खड़ा होना चाहूंगा। मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है, यह मेरे लिए एक और लड़ाई होगी। मुझे नहीं पता कि मुझे समर्थन मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं चुनाव लड़ने से नहीं डरता।'' उन्होंने कहा, ''अगर मुझे बदलाव करने का मौका मिलता है तो मैं अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक खिलाड़ी के रूप में संन्यास लेने जा रहा हूं। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा।''



भारत ने तीसरी बार जीता चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब

टीएनसी नेटवर्क

नई दिल्ली। टीम इंडिया ने रविवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इसी के साथ भारत ने सातवीं बार आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम किया। वहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाए। जिसके जवाब में भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए विजयी चौका लगाया।

252 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी हुई। गिल 50 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हुए। कुछ गेंद के बाद विराट कोहली दो गेंद के बाद विराट कोहली दो गेंद में एक रन ही बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। रोहित 83 गेंद में 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे। श्रेयस अय्यर ने 62 गेंद में 48 रन की पारी खेली। उन्होंने अक्षर के साथ 61 रन की साझेदारी की लेकिन 39वें ओवर में सेंटनर का शिकार बने। अक्षर 40 गेंद में 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हार्दिक पंड्या 18 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें काइल जैमीसन ने आउट किया। जबकि केएल राहुल और रविंद्र जडेजा नाबाद लौटे। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत सधी हुई थी। विल यंग और रचिन रविंद्र ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 57 रन की साझेदारी हुई। वरुण चक्रवर्ती ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने यंग (15) को पवेलियन का रास्ता दिखाया। रचिन रविंद्र 29 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। केन विलियमसन 14 गेंद में 11 रन ही बना पाए। टॉम लैथम ने 30 गेंद में 14 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 34 रन की पारी खेली। डेरिल मिचेल ने कीवी टीम के लिए सबसे ज्यादा 63 रन की पारी खेली। उन्हें शमी ने आउट किया। इसके बाद कप्तान मिचेल सैंटनर महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं माइकल ब्रेसवेल शतकीय पारी खेलकर नाबाद लौटे। टीम इंडिया की ओर से वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। फिलहाल, भारत को खिताब जीतने के लिए 252 रन चाहिए।



रोहित शर्मा तीसरे पायदान पर पहुंचे

आईसीसी ने खिलड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। ये रैंकिंग हाल ही में समाप्त हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद जारी हुई है जिसमें भारतीय टीम और खिलाड़ियों ने जमकर धूम मचाई है। इस वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने धमाल मचाया है। जबकि शुभमन गिल बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं। वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग में टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल अब भी टॉप पर काबिज हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं। तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को 2 पायदान का फायदा हुआ है और अब वो तीसरे नंबर पर हैं। साथ ही विराट कोहली एक पायदान फिसले हैं। वो अब 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में चार ही भारतीय काबिज हैं। गिल, कोहली और रोहित के अलावा चौथे भारतीय श्रेयस अय्यर हैं, जो 8वें नंबर पर मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को 14 पायदान का फायदा हुआ है। वो वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग में अब 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

श्रीदेवी की मर्जी के बिना फिल्मी दुनिया में आई थीं जाह्नवी कपूर



छह मार्च को बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने अपना 28वां जन्मदिन मनाया। जाह्नवी कपूर दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बड़ी बेटी हैं। उनको फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे 7 साल बीत चुके हैं। जान्हवी कपूर आज बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को जमकर टक्क र देती हैं। जाह्नवी कपूर ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के चलते उन्होंने लाखों दर्शकों के दिलों में जगह बनाई।

जन्म और परिवार

मुंबई में 06 मार्च 1997 को जाह्नवी कपूर का जन्म हुआ था। इनके पिता बॉलीवुड के फेमस फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर हैं। वहीं मां का नाम श्रीदेवी था। दिवंगत श्रीदेवी इंडस्ट्री की उन कलाकारों में से थीं, जिन्होंने अपने समय में बड़े-बड़े मेल सुपरस्टार्स को टक्कर दी है। श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था।

करोड़ों की मालकिन

जाह्नवी कपूर काफी आलीशान जिंदगी जीती हैं। उनके पास बहुत कम उम्र में अच्छी-खासी संपत्ति है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जाह्नवी कपूर की नेटवर्थ करीब 82 करोड़ रुपए है।

फिल्मी करियर

बता दें कि महज 20 साल की उम्र में जाह्नवी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा था। एक्ट्रेस ने साल 2018 में शशांक खैतान के निर्देशन में बनी धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में जाह्नवी कपूर के अलावा ईशान खट्टर नजर आए थे। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया और यह फिल्म हिट साबित हुई। एक्ट्रेस ने अपने 7 साल के फिल्मी करियर में करीब 10 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से अधिकतर फिल्मों को दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला।

उतार चढ़ाव भरा रहा करियर

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने घोस्ट स्टोरीज में नजर आई थीं, जोकि नेटफ्लिक्स पर नजर आई थीं। इसके बाद एक्ट्रेस गुंजन सक्सेनाः द कारगिल गर्ल में नजर आईं, जोकि हिट साबित हुई थी। साल 2021 में जाह्नवी कपूर की फिल्म रूही रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस के अपोजिट राजकुमार राव नजर आए थे। लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके अलावा अभिनेत्री फिल्म देवरा में नजर आई थीं, इस फिल्म में उनके साथ जूनियर NTR के साथ स्क्रीन साझा करती दिखीं। जूनियर ह्रञ्क और जाह्नवी कपूर के अलावा सैफ अली खान भी इस फिल्म में थे। वहीं जाह्नवी मिस्टर एंड मिसेज माही और उलझ जैसी फिल्मों में भी नजर आई हैं। ●



अलहदा है सिंगर शंकर महादेवन के गानों का ताप

पिता की मौत के बाद प्रियंका ने मां के लिए रखी थी बर्थडे पार्टी

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों एसएस राजामौली की फिल्म SSMB 29 के साथ इंडियन सिनेमा में एंट्री करने जा रही है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने लेहरन रेट्रो के दिए एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा कर दिया। इस इंटरव्यू में मधु ने उस पल को भी याद किया कि कैसे उनके पति की मौत के बाद प्रियंका ने जॉन अब्राहम के साथ मिलकर उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देते हुए बर्थडे पार्टी दी थी।



मधु चोपड़ा का बर्थडे बैश

मधु चोपड़ा ने खुलासा किया कि प्रियंका ने उनके पति अशोक चोपड़ा के मौत के 6 दिन बाद ही उनके लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने पर जोर दिया और उस पल को याद किया। मधु ने आगे बताया कि उनका निधन 10 जून को हुआ और मेरा जन्मदिन 16 जून को है। मैं 60 साल की होने वाली थी और प्रियंका ने मेरे लिए एक बड़ी पार्टी का प्लान बनाया था। पति की बीमारी के कारण पूरा परिवार पहले से ही वहां मौजूद था। उनके निधन के बाद, हम शोक में थे, लेकिन प्रियंका ने जोर देकर कहा कि हम पार्टी के साथ आगे बढ़ें और सभी को रुकने के लिए कहा। प्रियंका ने कहा, पिताजी यही चाहते थे।

प्रियंका चोपड़ा के अपकमिंग प्रोजेक्ट

प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली की फिल्म SSMB 29 में नजर आएगी। इस फिल्म में महेश बाबू भी है। बता दें कि, यह फिल्म इंडियाना जोन्स जैसी ही एक एक्शन-एडवेंचर है और यह इस साल जनवरी में हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। प्रियंका के पास जॉन सीना और इदरीस एल्बा के साथ हेड्स ऑफ स्टेट और रुसो ब्रदर्स की सीरीज सिटाडेल का दूसरा सीजन भी पाइपलाइन में है।

मधु चोपड़ा जॉन अब्राहम की फैन

मधु चोपड़ा खुलासा किया कि वह जॉन अब्राहम की बहुत बड़ी फैन हैं और आगे बताया कि, प्रियंका ने जॉन से आधी रात को आने का अनुरोध किया था और जॉन बर्थडे के गिफ्ट की तरह पैक होकर आए। कल्पना कीजिए! प्रियंका ने कहा, नहीं, मम्मी को अपना पल बिताना है। यह डीजे और म्यूजिक के साथ एक मजेदार पार्टी थी। लेकिन परिवार के बाकी लोग उदास होकर बैठे रहे, और कह रहे थे, उसे देखो! वह नाच रही है! क्या मधु अपने पति के लिए दुखी नहीं है? इस बीच, मैं सोच रही थी, मेरी बेटी ने यह सब व्यवस्थित किया है; मेरे बच्चों ने बहुत प्रयास किया है। वे सभी पीड़ित और दुखी हैं, लेकिन प्रियंका इस तरह से अपने पिता का सम्मान कर रही है। प्रियंका ने यहां तक कहा, मैं उनकी इच्छा का सम्मान कर रही हूं, और बेहतर होगा कि आप भी उनके साथ चलें। वह ऐसी ही इंसान हैं। मधु ने आगे बताया कि जॉन बो टाई पहने हुए आए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे।

बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। शंकर महादेवन अपनी सुरीली आवाज से लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं। वह एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ ही म्यूजिक कंपोजर भी हैं। शंकर महादेवन ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि अन्य कई भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू चलाया है। छोटी उम्र में ही उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रख दिया था। वहीं जब शंकर महादेवन महज 5 साल के थे, तभी से संगीत सीखना शुरूकर दिया था।

जन्म और शिक्षा

मुंबई के चेंबूर में तमिल परिवार में 01 मार्च 1967 को शंकर महादेवन का जन्म हुआ था। उनको बचपन से ही गाने का शौक था और इसके लिए उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। शंकर महादेवन ने मुंबई के चेम्बूर में ओएलपीएस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। लेकिन संगीत को लेकर महादेवन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। कॉलेज के दिनों में भी वह म्यूजिक से जुड़े रहे।

ब्रीथलेस से मिली पहचान

साल 1998 में शंकर की पहली एल्बम ब्रीथलेस उनके सिंगिंग करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। इस एल्बम से शंकर महादेवन को काफी फेम मिला था। जिसके बाद शंकर महादेवन ने एक के बाद एक कई फिल्मों के लिए गाने गाए। शंकर महादेवन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक म्यूजिक ग्रुप बनाया और संगीत के नए सफर की शुरूआत की।

सम्मान

सिंगर शंकर महादेवन को चार बार नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। शंकर को पहला नेशनल अवॉर्ड मशहूर सिंगर ए.आर रहमान के साथ तमिल फिल्म कांदोकंदनीं-कांदोकंदनीं के लिए मिला था। इसके अलावा उन्होंने तीन बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड भी जीता है। शंकर महादेवन को एक बार बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया।

इराक में सत्ता परिवर्तन के लिए ज़ायोनी और तकफ़ीरी ताकतें एक साथ आईं

एम. हसन

अभी तक प्रधानमन्त्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ समन्वय रूपरेखा गठबंधन काफ़ी मज़बूत दिखाई दे रहा है, लेकिन क्षेत्र और पश्चिम में अंदरूनी और बाहरी ताकतें इराकी शिया सरकार को हटाने के लिए सक्रिय हैं, क्योंकि यह तेहरान के साथ निकटता रखती है, जिसने दशकों की आर्थिक कठिनाई और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, बड़ी संख्या में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और गैस और तेल के निर्यात में लाखों डॉलर का निवेश किया था, इराक और ईरान से लौटने के बाद एम हसन लिखते हैं।

अक्टूबर 2025 में इराक में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के तेज़ी से नज़दीक आने के साथ, ज़ायोनी और तकफ़ीरी-वहाबी ताकतों ने संकटग्रस्त देश में शिया सत्तारूढ़ गठबंधन में बदलाव के लिए हाथ मिलाया है, जो सद्दाम हुसैन के दशकों के आतंकवादी शासन के बाद आर्थिक और राजनीतिक ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य इराक से ईरान को हटाना भी है। मध्य पूर्व में ये दोनों ही शिया सरकारें हैं। फिलहाल प्रधानमन्त्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ समन्वय फ्रेमवर्क गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, लेकिन क्षेत्र और पश्चिम में भीतर और बाहर की ताकतें तेहरान के साथ इसकी निकटता के कारण ÷इराकी शिया सरकार÷ को हटाने के लिए सक्रिय हैं, जिसने दशकों के आर्थिक कठिनाई और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लाखों डॉलर का निवेश किया था और गैस और तेल का निर्यात किया था। पिछले कुछ वर्षों में इराक इसका पहला ग्राहक बन गया है। एक अनुमान के मुताबिक दोनों देशों के बीच आर्थिक आदान-प्रदान प्रति वर्ष 12 अरब डॉलर से अधिक है। कर्बला और नजफ़ (दोनों इराक में) के अधिक शिया धार्मिक स्थल ईरानियों के साथ मजबूत बंधन शक्ति हैं, धार्मिक पर्यटन भी दोनों देशों के बीच अन्योन्याश्रय का एक तरीका है।

हालांकि, यह गैर-शिया तकफ़ीरी आबादी के लिए अभिशाप प्रतीत होता है, जो दशकों से सद्दाम हुसैन के शिया विरोधी शासन के तहत बढ़ी है, जब इस समुदाय को नरसंहार का सामना करना पड़ा और अरब दुनिया और पश्चिम ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इराक में, शिया मुसलमानों ने बहुमत का गठन किया, जो कि आबादी का 64-69त्न है, जबकि सुन्नी मुसलमान लगभग 29-



34त्न हैं। इसका मतलब है कि कुल आबादी का लगभग 61-64 प्रतिशत शिया और 29-34 प्रतिशत सुन्नी के रूप में पहचाने जाते हैं।

मुझे पिछले फरवरी में कर्बला की अपनी यात्रा के दौरान इस घृणा-घटना का व्यक्तिगत अनुभव हुआ, जब कुछ तकफ़ीरी हिंसक युवाओं ने मेरे समूह को घनी बाज़ार वाली जगह पर नमाज़ अदा करने से रोक दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 2003 में सद्दाम शासन के पतन के बाद सत्ता खोने पर उनके गहरे गुस्से और पीड़ा को दर्शाता है। इराकी बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत ईरान के खिलाफ भी हो गई है, जो देश का रक्षक बन गया है जब अन्य अरब देशों ने इसे आतंकवादियों (आईएसआईएस) की दया पर छोड़ दिया था। फिर भी, यह ईरान ही है जो इराकी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर देश के कुछ हिस्सों में इन आतंकवादियों के खिलाफ किला बनाए हुए है। ÷बहुसंख्यक समुदाय उस दृश्य को नहीं भूला है जब इन अपराधियों ने शिया इमाम अली अल-हादी (10वें इमाम) और उनके बेटे, इमाम हसन अल-अस्करी (11वें इमाम) की कब्र को उड़ा दिया था, जिससे समारा में मौत और तबाही मच गई थी÷ अब अत्यधिक सुरक्षित स्थान पर मेरी यात्रा के दौरान एक इराकी मौलवी ने टिप्पणी की।

इस प्रकार, इराकी समाज में सांप्रदायिक दरार गहरी है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि नजफ के शीर्ष मौलवियों द्वारा युद्धरत गुटों को एक साथ लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, मौजूदा स्थिति का लाभ उठाते हुए और अक्टूबर 2025 के राष्ट्रीय चुनावों पर नज़र रखते हुए, इराकी शियाओं के राजनीतिक वर्चस्व को खत्म करने के लिए और अधिक असंतोष पैदा करने की चालें चल रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह दूर की कौड़ी है क्योंकि समुदाय का अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व वापस मिल गया है। युद्धरत शिया राजनीतिक गुटों के बीच बड़े पैमाने पर अंदरूनी लड़ाई से इसे खोने की संभावना नहीं है। अतीत को देखते हुए वे सत्ता-साझेदारी पर एकजुट दिखाई देते थे।

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित एक लेख 'ईरान इराक खो सकता है' ने विस्तार से तर्क दिया है और दिशा-निर्देश दिए हैं कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। जिसने पर्याप्त संकेत दिए कि न केवल शत्रुतापूर्ण सुन्नी अरब दुनिया में बल्कि अन्य जगहों पर, जो क्षेत्र में ज़ायोनीवाद के हितों की सेवा करते हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए कमर कस रहे हैं। हालाँकि इराकी ऑनलाइन समाचार पत्रिका अशरक अल अवसत ने हाल ही में एक अध्ययन का हवाला देते हुए लिखा कि प्रधानमन्त्री सुदानी एक शक्तिशाली गठबंधन के साथ उभरेंगे जो संसद में शिया सीटों का एक तिहाई हिस्सा बनाएगा। अध्ययन ने बताया कि सुदानी ने हाल के महीनों में शिया शक्तियों के साथ लचीले गठबंधन बनाए हैं। सूत्र ने कहा कि समन्वय रूपरेखा ने गठबंधन बनाने वाली पार्टियों के बीच गहरी प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए इस तरह के गठबंधन बनाने की उनकी क्षमता को पूरी तरह से नहीं समझा है। सुदानी प्रभावी रूप से शिया समीकरण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे हैं और इस साल के आखिर में चुनावों के बाद संसद में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं। अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि पूर्व प्रधानमन्त्री नूरी अल-मलिकी के स्टेट ऑफ लॉ गठबंधन को संसदीय चुनावों में 25 सीटें मिलेंगी, अम्मार अल-हकीम के हिक्मा आंदोलन और पूर्व प्रधानमन्त्री हैदर अल-अबादी के नस्र गठबंधन को 21 सीटें मिलेंगी, तथा असैब अहल अल-हक पार्टी के नेता कैस अल-खजाली और बद्र संगठन के नेता हादी अल-अमेरी को 24 सीटें मिलेंगी, जबकि शेष सीटें अन्य शिया ताकतों को मिलेंगी। अध्ययन ने प्रभावशाली मौलवी मुक्तदा अल-सदर के नेतृत्व वाले सद्रिस्ट आंदोलन की संभावना को खारिज कर दिया, अगर वह मतदान में भाग लेने का फैसला करता है तो चुनावों में 70 से अधिक सीटें जीत सकता है। सद्र ने 2022 में राजनीतिक जीवन छोड़ दिया। उन्होंने 2021 के चुनावों में 70 से अधिक सीटें जीती थीं। सूत्रों ने कहा कि फ्रेमवर्क को उम्मीद है कि सद्र अधिकतम 60 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सद्र अब इराक में जनता को संगठित करने की क्षमता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं है। मलिकी और अन्य ने प्रांतीय चुनावों के बाद से इस दृष्टिकोण को अपनाने का फैसला किया था।

(लेखक हिंदुस्तान टाइम्स, लखनऊ, भारत के पूर्व ब्यूरो प्रमुख हैं)



Mahesh Singh Patel
Founder & Chairman
(BNCET)

BNCET

B.N. COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

AKTU Code-431
BTE Code-2260

NBA ACCREDITED | U.G. PROGRAM

B.Tech | M. Tech
MBA | Polytechnic

UPCOMING COURSES
BBA
BCA
(AFFLIATED FROM UNIVERSITY OF LUCKNOW)

Pharmacy
B.Pharm (code - 919)
D.Pharm (code - 2790)

NH-24, Sitapur Road, Bakshi Ka Talab, Lucknow - 226201 | 723 400 0903 • 723 400 0905 | Web: www.bncet.ac.in

MARUTI SUZUKI ARENA

पुरानी छोड़े, नई लाएं!

अपनी पुरानी कार स्क्रैप करें और भविष्य की ओर चलें।

ADDITIONAL SCRAPPAGE AND EXCHANGE BENEFITS UP TO ₹25 000^



BEST SCRAPPAGE VALUE* | BEST EXCHANGE OFFERS | UPTO 100% ON-ROAD FINANCE | 3 years 100 000 km WARRANTY** EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

विशेष ऑफर WAGONR ₹78 100* / ALTO K10 ₹83 100* / S-PRESSO ₹83 100* / BREZZA ₹35 000* SWIFT ₹58 100* / CELERIO ₹83 100* / EECO ₹38 100*

SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

T&C apply. Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on select models/variants. Above mentioned savings amount is the value of maximum savings on select models. Offer valid with select financiers only. **3 years or 100 000 km – whichever is earlier. ^Scrappage Offer valid for limited time only. For more details, please contact your nearest ARENA dealership. #Scrapage value offer is brought to you by Maruti Suzuki Toyotsu India Private Limited (a joint venture company between Maruti Suzuki India Ltd and Toyota Tsusho Group). Above offers are valid till 31st March 2025.

VISIT YOUR NEAREST MARUTI SUZUKI ARENA DEALERSHIP TODAY OR E-BOOK AT WWW.MARUTISUZUKI.COM | CALL 1800 102 1800